A Daily News Magazine
इंदौर
शनिवार, 23 मई, 2026

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 230, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

प्रसंगवश

अपराधमुक्त राजनीति से ही संभव है नया और विकसित भारत

ललित गर्ग

भारत आज एक ऐतिहासिक संक्रमण काल से गुजर रहा है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व राजनीति और कूटनीति के केंद्र में उभर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय राजनीति में अपराध, धनबल और बाहुबल की बढ़ती पैठ लोकतंत्र की आत्मा को आहत कर रही है। यह विडंबना ही है कि जिस भारत को विश्वगुरु बनने का स्वप्न दिखाया जा रहा है, उसकी राजनीति अभी भी अपराधमुक्त नहीं हो सकी है। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद सामने आए आंकड़ों ने इस चिंता को और गहरा कर दिया है। समाचार पत्रों में प्रकाशित एडीआर (ऐसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट) की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल विधानसभा के लगभग 65 प्रतिशत विधायक आपराधिक मामलों वाले हैं, जबकि 61 प्रतिशत विधायक करोड़पति हैं। रिपोर्ट के अनुसार 294 विधायकों में से 190 विधायकों ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले घोषित किए हैं तथा लगभग 142 विधायकों पर गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और अन्य गंभीर मामले भी शामिल हैं।

यह केवल पश्चिम बंगाल की स्थिति नहीं है। संसद और देश की अनेक विधानसभाओं की स्थिति भी इससे बहुत अलग नहीं है। पिछले कुछ वर्षों के चुनावी विश्लेषण बताते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित अनेक राज्यों में बड़ी संख्या में ऐसे जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं, जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं। लोकतंत्र के मंदिरों में अपराध और दागी छवि वाले लोगों की बढ़ती उपस्थिति आज राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुकी है। राजनीति मूलतः लोकसेवा, नैतिक नेतृत्व और राष्ट्रनिर्माण का माध्यम मानी गई थी। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने राजनीति को मूल्य आधारित दिशा दी। लेकिन समय के साथ राजनीति में वैचारिक प्रतिबद्धता का स्थान धीरे-धीरे चुनावी गणित, धनबल और प्रभावशाली समूहों ने लेना शुरू कर दिया। आज कई राजनीतिक दल उम्मीदवार चयन में योग्यता, चरित्र और जनसेवा की बजाय 'जीतने की क्षमता' को प्राथमिकता देते दिखाई देते हैं। यही कारण है कि दागी छवि वाले व्यक्तियों को भी टिकट देने में संकोच नहीं किया जाता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की राजनीति मंत आने के बाद अनेक मंचों से राजनीति के अपराधीकरण पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने संसद में और सार्वजनिक मंचों पर कई बार कहा कि राजनीति को अपराधमुक्त बनाना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष अदालतों की आवश्यकता पर बल दिया। किंतु चिंता का विषय यह है कि आज भी लगभग सभी राजनीतिक दलों की स्थिति समान दिखाई देती है। चुनाव जीतने की मजबूरी और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण दल अपराधी और दागी उम्मीदवारों को टिकट देने से परहेज नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला है चुनावों का अत्यधिक खर्चीला होना। आज चुनाव लड़ना सामान्य व्यक्ति की क्षमता से बाहर होता जा रहा है। बड़े संसाधनों वाले और आर्थिक रूप से प्रभावशाली लोग चुनावी प्रक्रिया में अधिक सक्रिय हो रहे हैं। दूसरा है बाहुबल और प्रभाव का उपयोग। तीसरा कारण है न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति। गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों के वर्षों तक लंबित रहने के कारण आरोपी चुनाव लड़ते रहते हैं और जनप्रतिनिधि बन जाते हैं।

राजनीति में अपराधीकरण का दूसरा बड़ा पक्ष है धनबल। पश्चिम बंगाल विधानसभा के आंकड़े बताते हैं कि 61 प्रतिशत विधायक करोड़पति हैं। यह प्रवृत्ति पूरे देश में दिखाई देती है। संसद और विधानसभाओं में करोड़पति जनप्रतिनिधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रश्न यह है कि क्या लोकतंत्र धीरे-धीरे सामान्य नागरिक की पहुंच से दूर होता जा रहा है? यदि राजनीति केवल धनवान और प्रभावशाली वर्गों तक सीमित हो जाएगी तो लोकतंत्र की समावेशी भावना कमजोर होगी। इन परिस्थितियों में नागरिक समाज और लोकतांत्रिक संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय मतदाता संगठन लंबे समय से राजनीति को स्वच्छ और अपराधमुक्त बनाने की दिशा में जनजागरण अभियान चला रहा है। इसी प्रकार एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट) जैसे संगठन भी चुनावी पारदर्शिता और जनप्रतिनिधियों की पृष्ठभूमि सार्वजनिक करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय चुनाव आयोग भी इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं। उम्मीदवारों को शपथपत्र में अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति और देनदारियों की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। चुनाव आयोग लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है। किंतु केवल औपचारिक प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। आज आवश्यकता है कि राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आंदोलन खड़ा किया जाए। इसके लिए कुछ ठोस कदम आवश्यक हैं- पहला, जिन उम्मीदवारों पर हत्या, बलात्कार, अपहरण, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप न्यायालय द्वारा तय हो चुके हों, उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने पर गंभीर विचार होना चाहिए। दूसरा, जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों के त्वरित निपटान हेतु विशेष न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि वर्षों तक मुकदमे लंबित न रहें। तीसरा, राजनीतिक दलों को दागी उम्मीदवारों को टिकट देने पर जवाबदेह बनाया जाए। चौथा, चुनावी खर्च पर कठोर नियंत्रण और पारदर्शिता लाई जाए ताकि सामान्य और योग्य नागरिक भी राजनीति में प्रवेश कर सकें। पांचवां, मतदाता जागरूकता को जनांदोलन बनाया जाए। भारत आज जिस दिशा में बढ़ रहा है, वहां राजनीति की शुचिता और नैतिकता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। यदि हम 2047 तक विकसित भारत बनना चाहते हैं, यदि हमें विश्वगुरु बनना है, यदि भारत को वैश्विक नेतृत्व करना है, तो राजनीति को अपराध और धनबल के प्रभाव से मुक्त करना ही होगा। आर्थिक शक्ति, तकनीकी प्रगति और वैश्विक प्रतिष्ठा तभी सार्थक होगी जब लोकतंत्र की आत्मा सुरक्षित रहेगी। राजनीति का उद्देश्य सत्ता प्राप्ति नहीं, समाज निर्माण होना चाहिए। लोकतंत्र केवल वोटों का गणित नहीं, बल्कि विश्वास, नैतिकता और जनप्रतिनिधित्व की पवित्र व्यवस्था है। यदि राजनीति अपराधमुक्त होगी तो शासन अधिक पारदर्शी होगा, जनता का विश्वास बढ़ेगा और राष्ट्रनिर्माण की गति भी तेज होगी।

आज आवश्यकता केवल सरकारों या चुनाव आयोग के प्रयासों की नहीं है, बल्कि समाज, मतदाता संगठनों, नागरिक संस्थाओं, मीडिया और जागरूक नागरिकों के संयुक्त अभियान की है। भारतीय मतदाता संगठन जैसे प्रयास इसी दिशा में आशा की किरण हैं। इन प्रयासों को राष्ट्रीय स्वरूप देने की जरूरत है। भारत के विकसित भविष्य की आधारशिला केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि स्वच्छ राजनीति भी है। क्योंकि अपराधमुक्त राजनीति ही विकसित भारत, समृद्ध भारत और विश्वगुरु भारत की वास्तविक पहचान बन सकती है।

(प्रभासाक्षी डॉट कॉम पर प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

शरद की सुबह

वही फिर गीत गाएँगे,
कभी तुम चाय पर आना
वो सरगम गुनगुनाएँगे,
कभी तुम चाय पर आना
तराने झूमते गाते थे
पलपल देखकर तुमको
उन्हें फिर से उठाएँगे,
कभी तुम चाय पर आना
वो स्वर्णिम पल कहाँ फिर
लौटकर वापस ही आएँगे
चलो यादें सजाएँगे,
कभी तुम चाय पर आना
कोई शिकवा कहीं तुम
दिल में लेकर तो नहीं बैठे
चलो दिल को मनाएँगे,
कभी तुम चाय पर आना
उदासी ओढ़कर बैठा है
ये दिल भी बहुत गुमसुम
तुम्हें सबकुछ बताएँगे,
कभी तुम चाय पर आना
समय को भी समय मिलता
नहीं अब तो न जाने क्यों
चलो कुछ पल चुराएँगे,
कभी तुम चाय पर आना
तुम्हारे साथ तो ये पल भी
कैसे खिलखिलाते थे
इन्हें फिर से हँसाएंगे,
कभी तुम चाय पर आना।

– डॉ.सीमा विजयवर्गीय

● देशभर में गर्मी बनी जानलेवा, 300 से ज्यादा हीटस्ट्रोक के मामले, उत्तर भारत में हीटवेव अलर्ट

दुनिया के सबसे गर्म 22 शहरों में सभी भारत के

● ट्रैक्टर-ट्रॉली को स्वीमिंग पूल बनाया, बांदा में ट्रैफिक सिग्नल बंद, कूलिंग सेंटर बनाए, राममंदिर में दरी बिछाई गई

नई दिल्ली/भोपाल/जयपुर/लखनऊ (एजेंसी)। देश को अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं। एक्यूआई वेदर के मुताबिक शुक्रवार दोपहर 3 बजे दुनिया के 22 सबसे गर्म शहरों में पारा 47 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। यह सभी शहर भारत के हैं। इनमें 13 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। ओडिशा का बोलांगीर और बिहार का सासाराम सबसे ज्यादा गर्म रहा।

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के 35 शहरों में गुरुवार को रात का पारा 30 डिग्री से ऊपर रहा- एक्यूआई वेदर के मुताबिक, दोपहर 3 बजे दुनिया के सबसे गर्म शहरों में 13 यूपी के हैं। पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इनमें वाराणसी, जौनपुर, अयोध्या, प्रयागराज, मुरादाबाद, मिर्जापुर शामिल हैं। बांदा में चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल बंद कर पुलिस की तैनाजी की गई है। ताकि लोगों को झुलसती धूप में रेड लाइट में खड़ा न होना पड़े। जगह-जगह कूलिंग सेंटर बनाए गए हैं। कूलर और ठंडे पानी के इंतजाम किए गए हैं। गोरखपुर में लोगों ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को स्वीमिंग पून बना लिया। काशी में बाबा विश्वनाथ का 24 घंटे जलाभिषेक किया जा रहा है। अयोध्या में भक्तों के लिए लाल मैट बिछाई गई है।

हिमाचल की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात

अन्य भागों में बारिश

हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बारिश और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात हुआ। लाहौल स्पीति के रोहतांग दर्रा, बारालाचा और शिंकुला टॉप में बर्फबारी हुई। इससे सड़कों पर फिसलन बढ़ गई और कुछ देर के लिए बर्फीला तूफान भी चला, जिससे कुछ पर्यटक भी फंस गए। मगर दोपहर बाद मौसम साफ होते ही वाहनों की आवाजाही दोबारा शुरू हुई। वहीं शिमला, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, ऊना, चंबा जिला समेत राज्य के अधिकांश भागों में आज बारिश हुई।

दिल्ली और उत्तर भारत में हीटवेव का खतरा

भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 22 से 27 मई के बीच दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में हीटवेव से लेकर गंभीर हीटवेव जैसी स्थिति बन सकती है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में हीटस्ट्रोक के दो मरीज भर्ती किए गए हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

आईआईएफएम में इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस समिट

मुख्यमंत्री बोले-टाइगर रिजर्व के आसपास वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर स्थापित करेंगे, बाइक और रेस्क्यू ट्रकों को दिखाई झंडी

भोपाल (नप्र)। प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के आसपास वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि घायल वन्य जीवों का उपचार स्थानीय स्तर पर ही हो सके। अब तक जंगल में घायल होने वाले जानवरों को इलाज के लिए भोपाल लाना पड़ता था, जिससे उन्हें अनावश्यक तकलीफ होती थी। स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू सेंटर बनने से वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से दूर नहीं ले जाना पड़ेगा और उनका उपचार भी तेजी से हो सकेगा।

यह बात शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कही। वे भोपाल स्थित आईआईएफएम में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस प्री-समिट को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने वन विभाग की 20 बाइक और एक रेस्क्यू ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

चीता प्रोजेक्ट ने मप्र को नई पहचान दिलाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, तब कई लोगों ने इसे लेकर आशंकाएं जताई थीं और डर का माहौल बनाया था, लेकिन अब इस परियोजना की सफलता ने मध्यप्रदेश को वन्य जीव विविधता के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी में मगरमच्छ नहीं होने की बात सामने आने पर यह चर्चा होती थी कि यदि वाहन मगरमच्छ नहीं है तो मां नर्मदा की सवारी कैसे होगी। शुरुआत में कोई भी मगरमच्छ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सरकार ने इस दिशा में भी कार्य पूरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल संरक्षण को लेकर लगातार काम कर रही है। जल गंगा संवर्धन अभियान लगातार तीसरे वर्ष चलाया गया है। इस अभियान के तहत करीब तीन हजार करोड़ रुपए की लागत से 56 हजार से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार और निर्माण किया गया है।

ट्विशा केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

एम्स दिल्ली की टीम करेगी दोबारा पोस्टमार्टम समर्थ की अग्रिम जमानत अर्जी वापस

जबलपुर(एजेंसी)। भोपाल के हाई-प्रोफाइल ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान कई अहम घटनाक्रम सामने आए हैं। मामले के मुख्य आरोपी समर्थ सिंह की ओर से उसके अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने का निवेदन किया, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए याचिका निरस्त कर दी। समर्थ के वकील ने बताया कि आरोपी जिला कोर्ट में सरेंडर कर देगा।

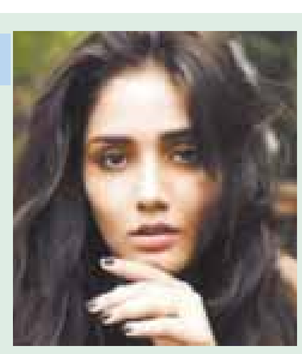

एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामला–

फरार पति समर्थ सिंह का जबलपुर कोर्ट में सरेंडर

देशभर में बहुचर्चित मॉडल ट्विशा शर्मा मौत मामले में शुक्रवार शाम बड़ा अपडेट आया है। मामले में फरार व मुख्य आरोपी ट्विशा का पति समर्थ शाम को अचानक जबलपुर जिला कोर्ट में सरेंडर करने वकील के साथ पहुंचा है। मामले में फिलहाल उसके सरेंडर की प्रक्रिया पूरी होने पर पुलिस समर्थ को भोपाल लेकर रवाना हो गयी है। ट्विशा शर्मा केस में मुख्य आरोपी ट्विशा का पति समर्थ सिंह के सरेंडर करने जबलपुर जिला कोर्ट पहुंचने की जानकारी सामने आई है। वह बीते 12 मई से पत्नी ट्विशा की मौत के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए भोपाल पुलिस ने 30 हजार रुपए इनाम रखा था। सुबह बड़े नाटकीय घटनाक्रम में समर्थ के वकील ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए लगाई गई याचिका वापस ले ली थी। बता दें कि हाईकोर्ट ने ट्विशा के शव का एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की अनुमति दे दी है।

बिहार की लड़की 'राधा रानी' बन पहुंची कान्स

● बिखेरी कृष्ण भक्ति की छटा, बांसुरी- मोर पंख लगा सान्या ने दिल जीता

नईदिल्ली(एजेंसी)। कान्स फिल्म फेस्टिवल में अब बिहार की बेटी का जादू छा गया है। 27 साल की एक्ट्रेस सान्या ठाकुर ने राधा रानी से प्रेरित लुक में रेड कार्पेट पर एंट्री ली, जो सिर्फ फैशन नहीं भारतीय संस्कृति को विदेशी मंच पर खूबसूरती से दर्शा गया। तभी तो जब से सान्या की तस्वीरें सामने आई हैं, लोग उन पर खूब प्यार बरसा रहे हैं।

जिसे सान्या ने बड़ी- ही खूबसूरती से स्टाइल किया और सिर से पैर तक कृष्णा रंग में रंगी नजर आईं। यही नहीं सान्या ने अपने लुक की हर एक डिटेल का खास ध्यान रखा, जो दिल जीत रही हैं। बांसुरी हो या फिर मोर पंख, सबकुछ लुक की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। तभी तो उनका लहंगे में देसी रूप लाइमलाइट में आ गया है। जिसे विदेशी भी रेड कार्पेट पर देखते रह गए। यकीन मानिए आपको भी उनका अंदाज किसी पौराणिक शो की याद दिला देगा।

एसबीआई-बैंक आज से 6 दिन तक रह सकते हैं बंद

नई दिल्ली (एजेंसी)। वीकेंड, कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल और बकरीद की छुट्टियों के कारण 23 से 28 मई तक एसबीआई में कामकाज प्रभावित रहेगा; डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई लगातार 6 दिनों तक बंद रह सकते हैं। 23 मई से 28 मई 2026 के बीच एसबीआई की ब्रांचों में कामकाज प्रभावित होगा।

पेट्रोल-डीजल पर वेट घटा सकते हैं राज्य

● तेलंगाना में सबसे ज्यादा लगता है टैक्स, 10 तक एक्साइज ड्यूटी घटा चुका केंद्र

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर पेट्रोल-डीजल सस्ता करने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार जल्द ही राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स (वेट) कम करने की अपील कर सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भाजपा शासित 22 राज्यों में वैट में कटौती की पूरी संभावना है। डीजल की कीमतों को नियंत्रित करना प्राथमिकता है, क्योंकि इसका सीधा असर परिवहन, खेती और उद्योग जगत पर पड़ता है।

सुबह सवेरे

इंदौर ■ शनिवार, 23 मई 2026

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20°c   न्यूनतम 18°c

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

टारगेट पूरा नहीं करने वाले अफसर-कर्मचारियों को पहले हटाया जाएगा

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश सरकार ने तबादला नीति-2026 जारी कर दी है। नई नीति में बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने तय लक्ष्य पूरे नहीं करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशासनिक आधार पर प्राथमिकता से हटाने का प्रावधान किया है। ऐसे कर्मचारी तीन साल की अवधि पूरी होने से पहले भी तबादले की सूची में शामिल किए जा सकेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद आदेश जारी कर 1 जून से 15 जून तक विभागों को तबादले की अनुमति दी है। महिलाओं और रिटायरमेंट में कम समय बचने वालों कर्मचारियों को राहत दी गई है।

तीन साल से पहले भी हो सकेगा तबादला- नई नीति के तहत प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कार्यपालिक अधिकारियों को एक ही जिले में तीन वर्ष पूरे होने पर जिले से बाहर स्थानांतरित किया जा सकेगा। वहीं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का भी एक स्थान पर तीन वर्ष या उससे अधिक समय पूरा होने पर तबादला किया जा सकेगा। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि तीन वर्ष की अवधि तबादले की अनिवार्य शर्त नहीं होगी। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी पिछले वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं कर पाया है तो उसका तबादला तय अवधि से पहले भी किया जा सकेगा। प्रशासनिक आधार पर ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने विभागों को यह भी निर्देश दिए हैं कि निर्माण और नियामक प्रकृति वाले विभागों को छोड़कर केवल तीन वर्ष की अवधि को तबादले का आधार न बनाया जाए।

माँ और शिशु स्वास्थ्य को लेकर प्रदेश की प्रगति राष्ट्रीय औसत से दोगुनी

एमएमआर में 38 अंकों की गिरावट, तकनीक आधारित निगरानी से प्राप्त हुए सकारात्मक परिणाम : शुक्ल

भोपाल नप्र। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हर माँ और हर नवजात का सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करना हमारी सरकार का संकल्प है। स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार, आधुनिक तकनीक के उपयोग और जमीनी स्तर तक सेवाओं की पहुँच के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश में मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। उन्होंने एसआरएस सर्वे में उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए स्वास्थ्य अमले को बधाई दी है एवं सतत प्रयास करते रहने का आह्वान किया है।

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए सतत प्रयासों के सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में मातृ मृत्यु दर में आई ऐतिहासिक गिरावट स्वास्थ्य तंत्र की प्रतिबद्धता, जमीनी स्तर पर कार्यरत अमले की मेहनत और आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली का परिणाम है। भारत सरकार के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार देश में मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) 2018-20 के 97 से घटकर 2022-24 में 87 प्रति एक लाख जीवित जन्म पर आ गया है। मध्य प्रदेश ने इस दिशा में राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रदेश का एमएमआर 2018-20 में 173 था, जो 2022-24 में घटकर 135 रह गया है। यह 38 अंकों यानी लगभग 22 प्रतिशत की गिरावट है, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुनी से भी अधिक है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, प्रशिक्षित डॉक्टरों एवं स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आपातकालीन प्रसूति सेवाओं के विस्तार से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए है।

प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना को लगातार सुदृढ़ किया गया है। प्रसव केंद्रों, प्रसूति गहन देखभाल इकाइयों (ऑब्सटेट्रिक एचडीयू), एफआरयू और सीईमॉनसी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। ब्लड स्टोरेज यूनिट्स की स्थापना और रेफरल परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने से गर्भवती महिलाओं को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध हो रहा है। तकनीक आधारित स्वास्थ्य सेवाओं ने भी मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एएनएमओएल 2.0 एप्लीकेशन के माध्यम से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का रियल-टाइम पंजीयन, जांच और फॉलो-अप सुनिश्चित किया जा रहा है।

संक्षिप्त समाचार

गंगा में नहाते-नहाते युवक ने बीयर पी, एफआईआर

● वाराणसी पुलिस गिरफ्तार करने बिहार जाएगी, 5 साल तक की सजा हो सकती है

वाराणसी (एजेंसी)। काशी में गंगा नदी में इफ्तार पार्टी के बाद शुक्रवार को बीयर पीने का मामला सामने आया है। अस्सी घाट गंगा में नहा रहे एक युवक ने बीयर पी। फिर केन को मोड़कर गंगा के तट पर फेंक दिया। युवक की इस करतूत को किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। उसे नदी से बाहर अपने पास बुलाया और फटकार लगाई। आरोपी युवक ने माफी मांगी। उसने कहा, गलती हो गई। अब आगे से ऐसा नहीं करूंगा। वीडियो सामने आने के बाद वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में युवक पर केस दर्ज किया है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम लगाई गई है। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी युवक बिहार के रोहतास जिले का रहने वाला है।

पाकिस्तान-बांग्लादेश सीमा पर 'स्मार्ट बॉर्डर' सुरक्षा सिस्टम लागू होगा, ड्रोन, रडार, स्मार्ट कैमरे लगेंगे

● अमित शाह बोले- हर अवैध घुसपैठिए को देश से बाहर निकालेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार अगले एक साल के भीतर पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी करीब 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर 'स्मार्ट बॉर्डर' सुरक्षा सिस्टम लागू करेगी। इसके तहत ड्रोन, रडार, स्मार्ट कैमरे और दूसरी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सीमा की निगरानी मजबूत की जाएगी, ताकि घुसपैठ और तस्करी को पूरी तरह रोका जा सके। दिल्ली में बीएसएफ के रुसतमजी मेमोरियल लेक्चर और बीएसएफ इन्वेस्टिचर सेरेमनी को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि सरकार की अवैध घुसपैठ को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति है। उन्होंने कहा कि देश में मौजूद हर अवैध घुसपैठिए की पहचान की जाएगी और उसे वापस भेजा जाएगा।

सीएम शुभेंदु बोले-

अवैध बांग्लादेशियों को सीधे बीएसएफ को सौंपेंगे

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य में पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अब कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। उन्हें सीधे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंप दिया जाएगा। नया नियम 20 मई से लागू हो गया है।

बंगाल में सोना पप्पू के खिलाफ केस में ईडी ने 9 जगह छापा मारा, पूर्व डीसीपी के घर ताला तोड़कर घुसी टीम

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर नए छापे मारे। ये छापे कोलकाता पुलिस के गिरफ्तार अधिकारी शांतनु सिन्हा बिस्वास और कथित अपराधी बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत मारे गए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं केंद्रीय वन मंत्री यादव ने एबीएस एंड-टू-एंड वेब पोर्टल का किया शुभारंभ

मध्यप्रदेश वैश्विक वन्य जीव संरक्षण का बना रोल मॉडल : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जैव-विविधता में हमारा प्रदेश, देश में एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में विकसित किया जा रहा है। हमारे पास 'टाइगर स्टेट', 'लेपर्ड स्टेट', 'चीता स्टेट', 'वल्चर स्टेट', 'घड़ियाल स्टेट', 'वुल्फ स्टेट' का टाइटल है। सालों पहले देश की धरती से चीते लुप्त हो चुके थे। हम देश की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पहचाने जाने वाले चीतों को प्रदेश की धरती में वापस ले आये हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश को चीता स्टेट बनने का गौरव देने के लिए केन्द्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि चीतों ने पालपुर कूनो और गांधी सागर अभयारण्य को अपना घर मान लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में अब कुल 53 चीते हैं। मध्यप्रदेश वैश्विक वन्यजीव संरक्षण का सबसे बड़ा और वैज्ञानिक रोल मॉडल बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस के अवसर पर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम) में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम एवं चीता संरक्षण पर मीडिया वर्कशाप को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारा मध्यप्रदेश 'मोगली लैंड' और 'सफेद शेरों की धरती' के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 100 साल के बाद मध्यप्रदेश की धरती पर जंगली भैंसे का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की गई है। दुर्लभ प्रजाति के 33 कछुए और 53 घड़ियाल कूनो नदी में छोड़े गए हैं। हलाली डेम क्षेत्र में 5 लुप्तप्राय गिद्धों को उनके नैसर्गिक वातावरण में मुक्त किया गया है।

जैव-विविधता है भारतीय सभ्यता की आत्मा - केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री यादव

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि भारत की प्राचीन नदी सभ्यताओं में नर्मदा का विशेष स्थान है। प्रदेश में अमरकंटक और पातालकोट धरती पर ईश्वर का दिया सबसे बड़ा उपहार है। जैव-विविधता हमारी भारतीय सभ्यता की मूल आत्मा है, इन्हें बनाए रखना ही हमारा संकल्प है, हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि जिसे हम बना नहीं सकते, कम से कम उसे बिगाड़े तो नहीं। धरती पर उपलब्ध जैव-विविधता से हमें भोजन, दवाई और जीवन मिलता है। दुनिया में हम धरती का 2.4 प्रतिशत भू-भाग रखते हैं। भारत में 36 हजार समृद्ध वनस्पतियां हैं, लेकिन यह वैश्विक स्तर पर केवल 8 प्रतिशत के आसपास है। 'प्रोजेक्ट चीता' में हमने एक वन्यजीव प्रजाति का संरक्षण किया है।

जल संरक्षण के लिये चलाया जा रहा महाअभियान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार जल संरक्षण की दिशा में भी तेजी से कार्य कर रही है। प्रदेश में गुड़ी पड़वा से लेकर गंगा दशहरा तक 3 महीने का जल संरक्षण महाभियान चल रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रदेश में बड़े पैमाने पर कार्य हो रहा है। राज्य में अब तक 3000 करोड़ रुपये की लागत से 56 हजार जल स्त्रोतों का जीर्णोद्धार और निर्माण, 827 बावड़ी, 1200 से अधिक तालाब, 212 नदियों में साफ-सफाई के कार्य किए गए हैं। इस महाभियान में प्रदेश के 18 लाख लोगों ने अपनी भागीदारी की है। जल और जंगल के संरक्षण तथा जमीन उर्वरता बचाए रखने में मध्यप्रदेश देश में नंबर वन है। प्रदेश में 2 लाख से अधिक जलदूत बनाए गए और एक हजार अमृत सरोवर का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। प्रदेश के पाँच हजार जलस्त्रोतों का विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में सरीसृपों की बसाहट का कार्य भी हो रहा है। प्रदेश में अब किंग कोबरा के साथ गैंडा लाने की भी तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जंगलों और राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास भी वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर वन्य जीवों को तत्काल इलाज की सुविधा मिल सके।

समान नागरिक संहिता- 15 जून तक आम जनता के लिए जाएंगे सुझाव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया वेबसाइट का लोकार्पण

भोपाल नप्र। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि समान नागरिकता संहिता के संबंध में प्रदेश में प्राप्त सुझावों के संकलन के लिए की गई पहल सराहनीय है। जनता के मत प्राप्त करने के लिए बनाई गई वेबसाइट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। जिलों में समान नागरिक संहिता समिति के भ्रमण से यह कार्य आसान होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में समान नागरिक संहिता मध्यप्रदेश की वेबसाइट का विमोचन किया। इस तरह की वेबसाइट के निर्माण में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समान नागरिक संहिता समिति के सदस्यों को वेबसाइट के निर्माण के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर राज्यों में इस संबंध में कार्य प्रारंभ हुआ है। स्वतंत्रता के बाद से ही इस तरह के कार्य की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए पारिवारिक विधि के समग्र अध्ययन की जरूरत है। जन सामान्य, राजनीतिक दल, गैर शासकीय संगठन आदि इस संबंध में अपना मत प्रस्तुत करेंगे, जिनका सम्मान करते हुए विचार मंथन होगा। सभी सुझावों का संकलन भी किया जाएगा। जन परामर्श के उद्देश्य से समिति ने वेबसाइट का निर्माण कर महत्वपूर्ण कार्य किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश एक राष्ट्र, एक विधान,एक निशान के महत्व को समझते हुए इसके अलावा 'एक विधि' के लिए आवश्यक दायित्व पूर्ण करेगा। निश्चित ही यह जन हितैषी कार्य है। इस नाते गठित समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति बधाई की पात्र है।

राज्य शासन द्वारा विवाह, भरण पोषण, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार एवं अन्य परिवार संबंधित कानूनों से संबंधित विधिक, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर समान नागरिक संहिता के संबंध में उपयुक्त अनुशंसाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। इस उद्देश्य से ही उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है विस्तृत अध्ययन के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता के संबंध में उपयुक्त अनुसंधान प्रस्तुत करने के लिए यह समिति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस अवसर पर समिति द्वारा जन परामर्श के उद्देश्य से निर्मित की गई वेबसाइट https//ucc.mp.gov.in/ पर जनमानस से सुझाव सुगमता से प्राप्त किए जा सकेंगे। सुझाव देने की अंतिम तिथि 22 मई से आगामी 15 जून 2026 तक निर्धारित की गई है।

वेबसाइट लांच किए जाने के अवसर पर समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्रीमती प्रकाश रचना देसाई ने भी वर्चुअली संबोधित किया। समिति के सचिव श्री अजय कटेसरिया ने समिति के कार्यों का विवरण दिया। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

माता-पिता आईएएस तो बच्चों को आरक्षण क्यों: सुप्रीम कोर्ट

क्रीमी लेयर के बच्चे रिजर्वेशन लेते रहे तो इससे कभी नहीं निकल पाएंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी नौकरी में क्रीमी लेयर के कैंडिडेट के आरक्षण लेने पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा- अगर माता-पिता दोनों आईएएस अफसर हैं, तो उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए?

शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ सामाजिक गतिशीलता भी आती है। ऐसे में अगर संपन्न बच्चों के लिए फिर से आरक्षण मांगा जाए, तो हम कभी भी इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने ये कमेंट तब किया। जब वे कर्नाटक हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिकाकर्ता को क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया था। क्योंकि उसके माता-पिता दोनों ही राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। यह मामला कर्नाटक में 'कुरुबा' समुदाय से जुड़े एक उम्मीदवार का है। कर्नाटक के पिछड़े वर्गों की सूची में इस समुदाय को 'श्रेणी II(A)' के तहत रखा गया है।

एनसीईआरटी किताब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने पुराना आदेश बदला- एनसीईआरटी बुक में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' चैप्टर पर हुए विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने पहले दिया फैसला बदल दिया है। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिन तीन शिक्षाविदों ने विवादित हिस्सा लिखा। उन्हें हटा दिया जाए और दोबारा काम न दिया जाए।अब शुक्रवार को तीनों शिक्षाविदों की याचिका पर कोर्ट ने आदेश बदलते हुए कहा कि केंद्र, राज्य, यूनिवर्सिटी और सरकारी फंड पाने वाले संस्थान इस मामले में खुद फैसला लें।

सीबीएसई की थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पेरेंट्स, जस्टिस जॉयमाल्या की बेंच करेगी सुनवाई

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को 19 लोगों के एक ग्रुप ने चुनौती दी। जिसमें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स शामिल हैं। ये याचिका क्लास 9वीं में थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू किए जाने के विरोध दायर की गई। इसके खिलाफ स्ष्ट अलगे हफ्ते सुनवाई करेगा। सीबीएसई ने 15 मई को एकेडमिक सेशन 2026-27 से थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने का सर्कुलर जारी किया था।इसका नोटिफिकेशन 1 जुलाई से लागू होगा और स्टूडेंट्स को 31 मई तक तीसरी लैंग्वेज चुनने का समय दिया गया है। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने इस मामले में पेरेंट्स की तरफ से पक्ष रखा। जस्टिस जॉयमाल्या और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बैच इस पर सुनवाई करेगी।

होर्मुज में जहाजों से फीस वसूलने की तैयारी में ईरान

ओमान के साथ पेमेंट सिस्टम पर बातचीत जारी, अमेरिका बोला- यह मंजूर नहीं

तेल अवीव/ तेहरान/ वॉशिंगटन डीसी (एजेंसी)। ईरान और ओमान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर फीस वसूली के सिस्टम को लेकर बातचीत कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नई बनाई गई पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने कहा कि उसने होर्मुज स्ट्रेट के 'मैनेजमेंट सुपरविजन एरिया' की सीमा तय कर दी है। अथॉरिटी के मुताबिक, यहां से गुजरने के लिए परमिट जरूरी होगा। फरवरी में अमेरिकी और इजराइली हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल ट्रैफिक लगभग रोक दिया था। इससे अंतरराष्ट्रीय शिपिंग प्रभावित हुई और ऊर्जा कीमतों में तेजी आई। इसके बाद ईरानी अधिकारियों ने इस जलमार्ग से राजस्व जुटाने के विकल्पों पर चर्चा शुरू की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है और यहां किसी तरह का टोल नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी इसका विरोध किया।

अहमदाबाद के कमर्शियल बिल्डिंग में लगी भीषण आग

● 50 लोगों को सुरक्षित बचाया गया

नई दिल्ली (एजेंसी)। अहमदाबाद के मकरबा इलाके में स्थित 11 मंजिला 'सॉलिटेयर बिल्डिंग' के टावर B की तीसरी मंजिल पर शुक्रवार दोपहर को भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया। अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के डिविजनल फायर ऑफिसर एस.बी. जडेजा ने बताया कि आग लगने के तुरंत बाद करीब 10 फायर टेंडर को मौके पर भेजा गया।

राज्यसभा की 26 सीटों पर 18 जून को चुनाव

नई दिल्ली। 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को चुनाव होगा। चुनाव आयोग (ईडी) ने शुक्रवार को यह ऐलान किया। रिटायर हो रहे सदस्यों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह, पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा समेत 24 सांसद शामिल हैं। इन सभी सीटों से मौजूदा सदस्य 21 जून से 19 जुलाई के बीच रिटायर हो रहे हैं। इनके अलावा, दो रिक्त सीट पर भी उपचुनाव होगा।

माणिकबाग ब्रिज के नीचे शोरूम में सेंध

इंदौर। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में माणिकबाग ब्रिज के नीचे स्थित एक रेडीमेड गारमेंट शोरूम में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात बदमाशों ने शटर के ताले तोड़कर दुकान में सेंध लगाई और कीमती गारमेंट्स, एक आईफोन 17 और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। गुरुनानक कॉलोनी, अन्नपूर्णा निवासी हरीश कुकरेजा की 'एल एन कलेक्शन' दुकान में यह वारदात हुई। व्यापारी ने स्टॉक मिलान किया तो 56 नग महंगे कपड़े गायब मिले। इसके बाद बारीकी से जांच करने पर चोरी का खुलासा हुआ। बदमाश शटर उचकाकर अंदर घुसे और कपड़ों के साथ मोबाइल, चार्जर, माइक व गल्ले में रखी करीब 10 हजार रुपये की नकदी भी चुरा ले गए। सूचना पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल और मानव हाइट्स परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी।

घर में घुसकर उत्पात, मारने की धमकी

इंदौर। अभिनंदन नगर क्षेत्र में एक रसूखदार युवक द्वारा घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाने और एक परिवार को धमकाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस के अनुसार पीड़ित शिबू जॉर्ज पिता पीएम जॉर्ज, जो ट्रेवल एजेंसी संचालित करते हैं, ने हीरानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया कि 20 मई की शाम करीब 7:57 बजे वह अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद थे। इसी दौरान कल्पना नगर निवासी आदर्श सोनी पुरानी रंजिश के चलते अचानक गुस्से में उनके घर पहुंचा और बिना किसी अनुमति के अंदर घुस गया। आरोपी ने घर में प्रवेश करते ही गाली-गलौज शुरू कर दी और विरोध करने पर आक्रोशित हो गया। उसने घर की खिड़कियों पर हमला करते हुए एक-एक कर सभी कांच तोड़ दिए, जिससे घर में अफरा-तफरी मच गई। भयभीत परिवार ने किसी तरह खुद को एक कमरे में बंद कर अंदर से दरवाजा लॉक कर अपनी जान बचाई।

रेडिसन क्षेत्र में युवती से मोबाइल लूटा

इंदौर। विजयनगर थाना क्षेत्र के रेडिसन सर्विस रोड पर बाइक सवार दो बदमाशों ने पैदल जा रही युवती से मोबाइल लूट लिया। घटना किल्लू ढाबे के सामने कट पॉइंट के पास हुई। पीड़िता प्रियंका श्रीवास्तव, ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया वह सड़क से गुजर रही थीं पीछे से तेज रफ्तार बाइक पर आए दो अज्ञात युवकों ने उनकी रेकी की। जैसे वह कट पॉइंट पर पहुंचीं बाइक सवारों ने अपनी गति धीमी कर अचानक हाथ में मौजूद मोबाइल पर झपट्टा मार दिया और मोबाइल छीन कर फरार हो गए। घटना के बाद युवती ने शोर मचाया लेकिन आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। आसपास के कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

बीजेपी नगर अध्यक्ष को दिल का दौरा

इंदौर। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें शहर के ज्यूपिटर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार, उन्हें दिल से संबंधित गंभीर समस्या (हार्ट प्रॉब्लम) होने के चलते अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की। शुरुआती मेडिकल जांच और एंजियोग्राफी में सुमित मिश्रा के दिल की धमनियों में गंभीर ब्लॉकेज की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि उनकी दो धमनियों में 90 प्रतिशत और एक अन्य धमनी में 50 प्रतिशत तक ब्लॉकेज पाया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर करने का फैसला लिया है। नगर अध्यक्ष को शुक्रवार को विमान के जरिए दिल्ली शिफ्ट किया गया। दिल्ली में देश के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक सेठ उनकी एंजियोप्लास्टी करेंगे और आगे की सर्जरी को अंजाम देंगे।

करंट लगने से छात्रा की मौत, 3 पर केस

इंदौर। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में करंट लगने से 13 साल की छात्रा की मौत हो गई। पुलिस जांच में लापरवाही पूर्ण बिजली कनेक्शन सामने आने के बाद तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। घटना 25 अप्रैल की है। पुलिस के मुताबिक सुख निवास निवासी मान्या पुत्री संतोष भाटी की मौत टेंट में फैले करंट की चपेट में आने से हुई। जांच में सामने आया कि टेंट में बिजली कनेक्शन लापरवाही से लगाया गया था। पुलिस जांच में पता चला कि कार्यक्रम स्थल पर पुराने और कटे तारों का उपयोग किया गया था। इसी वजह से करंट टेंट के पाइप में फैल गया और मान्या उसकी चपेट में आ गई। पुलिस ने जांच के बाद सुभाष सोनाने निवासी नार्थ मोहल्ला, श्रवण परमार और विनोद राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। परिजनों ने बताया कि मान्या आठवीं कक्षा में पढ़ती थी। उसके पिता प्रॉपर्टी का काम करते हैं।

12 से ज्यादा लोगों को हथियार दिए

इंदौर। राजेन्द्र नगर पुलिस ने तीन दिन पहले ममता नगर के पास एक युवक को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई टीआई यशवंत बडोले की टीम ने की थी। आरोपी की पहचान अक्षय शर्मा निवासी द्वारकापुरी के रूप में हुई। पुलिस ने अक्षय शर्मा को ममता नगर के पास से पिस्टल के साथ पकड़ा था। इसके बाद उसे थाने लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान अक्षय शर्मा ने बताया कि पिस्टल उसे चेतन नाथ निवासी अहीरखेडी ने बेची थी। अक्षय के बयान के अनुसार चेतन नाथ पिछले दो महीनों में इलाके में करीब एक दर्जन से अधिक लोगों को पिस्टल बेच चुका है। राजेन्द्र नगर पुलिस ने चेतन नाथ के ठिकाने पर दबिश दी, लेकिन वह मौके से फरार मिला। उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार चेतन नाथ पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसे अतुल बंसल हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। वह हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। जानकारी के मुताबिक चेतन नाथ द्वारकापुरी की ड्रग माफिया सीमा नाथ का भाई है। उस पर इलाके में अवैध कारोबार से जुड़े होने के आरोप हैं।

बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर के बीच स्पेशल ट्रेन

इंदौर। यात्रियों की सुविधा एवं ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान बढ़ती यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा रतलाम मंडल से बांद्रा टर्मिनस - गोरखपुर के मध्य स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ट्रेन संख्या 09157 / 09158 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर गोरखपुर- बोरीवली स्पेशल ट्रेन संख्या 09157 बांद्रा टर्मिनस -गोरखपुर स्पेशल रविवार 24 मई,2026 को 00:30 बजे बांद्रा टर्मिनस से चलकर रतलाम मंडल के रतलाम (10:22/10:32 रविवार) एवं नागदा (11:30/11:32 रविवार) होते हुए सोमवार को 17:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09158 गोरखपुर-बोरीवली स्पेशल सोमवार, 25 मई, 2026 को 20:30 बजे गोरखपुर से चलकर रतलाम मंडल के नागदा एवं रतलाम होते हुए बुधवार को 11:30 बजे बोरीवली पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, बयाना, भरतपुर, मथुरा, हाथरस सिटी, कासगंज, बरेली सिटी, इज्जत नगर, पीलीभीत, मैलानी, सीतापुर, बुढ़वल, गोंडा, बस्ती, एवं खलीलाबाद स्टेशनों पर रुकेगी।

खुले में शराब पीने वालों पर कार्रवाई

महू। महू थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और सार्वजनिक स्थानों पर खुले में नशा करने वाले असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व एसडीओपी और थाना प्रभारी ने किया,जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल रहा।

इंदौर में जल संकट गहराया, जिला प्रशासन सतर्क, पेयजल व्यवस्था सुधारने के निर्देश

अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन की मौजूदगी में व्यवस्था पर अहम बैठक

इंदौर। शहर में लगातार बढ़ती गर्मी और कई इलाकों में सामने आ रही पेयजल समस्या को लेकर प्रशासन ने गंभीरता दिखाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को रेसीडेंसी कोठी में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या अधिक है, वहां टैंकरों की संख्या बढ़ाकर नियमित रूप से पानी पहुंचाया जाएगा, ताकि नागरिकों को राहत मिल सके। बैठक में सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, शहर के विधायक, कलेक्टर शिवम वर्मा, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल सहित प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने अलग-अलग क्षेत्रों में सामने आ रही जल समस्या और उसके समाधान पर चर्चा की।

अधिकारियों को सख्त निर्देश

बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि गर्मी के इस दौर में किसी भी क्षेत्र में पेयजल संकट की स्थिति नहीं बनने दी जाए। जिन इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित हो रही है, वहां तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रशासन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर पानी के टैंकरों की संख्या और बढ़ाई जाएगी तथा उनकी नियमित निगरानी भी की जाएगी, ताकि वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इसके साथ ही नागरिकों से मिलने वाली शिकायतों के त्वरित निराकरण पर भी विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों से कहा गया कि जिन क्षेत्रों से बार-बार पानी की समस्या की शिकायत सामने आ रही हैं, वहां अलग से निगरानी रखी जाए और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

जल आपूर्ति पर बढ़ा दबाव

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बैठक में शहर की वर्तमान जल स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में जितना नर्मदा जल शहर की टंकियों तक पहुंचता था, लगभग उतनी ही मात्रा आज भी मिल रही है, जबकि इस दौरान शहर की आबादी और विस्तार दोनों तेजी से बढ़े हैं। नई कॉलोनियों और आबादी बढ़ने से जल वितरण व्यवस्था पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका असर कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। महापौर ने यह भी कहा कि जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पाइप लाइन सुधार, रखरखाव और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। उन्होंने इसके लिए 50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की मांग रखी।

संवेदनशील इलाकों पर निगरानी

बैठक में यह भी तय किया गया कि जिन क्षेत्रों में हर वर्ष गर्मी के दौरान पेयजल संकट की स्थिति बनती है, वहां प्रशासन विशेष निगरानी रखेगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पानी के टैंकर समय पर पहुंचे और वितरण व्यवस्था पारदर्शी रहे। किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि शहरवासियों को गर्मी के दौरान पेयजल संकट से राहत दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और जल आपूर्ति व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए लगातार समीक्षा की जाएगी।

डिजिटल साक्ष्यों से खुलेंगे कई राज हनी ट्रैप जांच में बड़े नामों की चर्चा

मोबाइल रिकॉर्ड और वीडियो की पड़ताल में जुटी क्राइम ब्रांच

इंदौर। शहर में सामने आए चर्चित हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग प्रकरण की जांच अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है, जहां से कई बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है। क्राइम ब्रांच को आरोपियों के मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों से बड़ी मात्रा में वीडियो, फोटो, आवाज रिकॉर्डिंग और बातचीत का विवरण मिला है। इन साक्ष्यों की जांच के बाद अब यह आशंका जताई जा रही है कि यह गिरोह लंबे समय से योजनाबद्ध तरीके से लोगों को जाल में फंसा रहा था। जांच एजेंसियां फिलहाल बरामद सामग्री को सार्वजनिक करने से बच रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी परीक्षण और दस्तावेजों की पुष्टि पूरी होने के बाद ही पूरे नेटवर्क और उससे जुड़े लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी। यह मामला शराब कारोबारी हितेंद्र को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने से जुड़ा है, जिसकी जांच लगातार आगे बढ़ रही है।

भाजपा नेत्री का नाम आया

जांच के दौरान सागर निवासी भाजपा नेत्री रेशू चौधरी का नाम सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया। क्राइम ब्रांच ने उसे आरोपी बनाया है। पुलिस के अनुसार रेशू चौधरी नेताओं, कारोबारियों और अधिकारियों तक पहुंच बनाकर उन्हें जाल में फंसाने में सक्रिय भूमिका निभाती थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह पहले लोगों के आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें तैयार करवाता था। इसके बाद उन्हीं सामग्रियों को आधार बनाकर दबाव बनाया जाता और मोटी रकम की मांग की जाती थी। अधिकारियों का मानना है कि गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था और इसके तार कई प्रभावशाली लोगों तक जुड़े हो सकते हैं।

भोपाल से संचालित था पूरा गिरोह

क्राइम ब्रांच की पड़ताल में यह तथ्य भी सामने आया है कि गिरोह की गतिविधियों का संचालन भोपाल से किया जा रहा था। डीसीपी राजेश त्रिपाठी के अनुसार मुख्य आरोपी श्वेता विजय जैन और रेशू चौधरी का संपर्क कई रसूखदार लोगों तक फैला हुआ था। जांच में मिले मोबाइल संदेश, व्हाट्सएप बातचीत, आवाज रिकॉर्डिंग और वीडियो सामग्री का इस्तेमाल लोगों पर दबाव बनाने के लिए किया जाता था। पुलिस अब यह जानने में जुटी है कि इस नेटवर्क के जरिए अब तक कितने लोगों को निशाना बनाया गया और उगाही की रकम कितनी थी।

पुराने प्रकरण से जुड़े तार

मामले में इंदौर निवासी अलका दीक्षित, उसका बेटा जयसिंह, पुलिस आरक्षक विनोद शर्मा, प्रॉपर्टी कारोबारी लाखन और वर्ष 2018 के चर्चित हनी ट्रैप मामले में आरोपी रही श्वेता जैन को भी आरोपी बनाया गया है। प्रारंभिक जांच में यह जानकारी सामने आई है कि जेल में रहने के दौरान श्वेता जैन और अलका दीक्षित की कई बार मुलाकात हुई थी। पुलिस को संदेह है कि उसी दौरान नए ब्लैकमेलिंग नेटवर्क की रूपरेखा तैयार की गई थी। इस जानकारी के सामने आने के बाद जांच एजेंसियां पुराने मामलों के दस्तावेज भी खंगाल रही हैं।

रिकॉर्डिंग की तकनीकी जांच - क्राइम ब्रांच अब आरोपियों के मोबाइल फोन, बातचीत के रिकॉर्ड और वीडियो सामग्री की गहन तकनीकी जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गिरोह का नेटवर्क किन शहरों तक फैला हुआ था और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे। अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे डिजिटल साक्ष्यों की परतें खुलेंगी, वैसे-वैसे कई नए नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां हर पहलू को सावधानी से परख रही हैं ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।

60 लाख की चोरी मामले में पीड़िता पर दबाव, बयान बदलने की धमकी

रिश्तेदारों पर समझौते का दबाव, जान से मारने की धमकी

इंदौर। बाणगंगा थाना क्षेत्र में 60 लाख रुपए की चोरी के चर्चित मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। चोरी की पीड़िता ने अपने ही रिश्तेदारों पर अदालत में बयान बदलने का दबाव बनाने, अभद्रता करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार कुम्हार खाड़ी निवासी मनीषा यादव के घर 7 फरवरी 2026 को बड़ी चोरी की वारदात हुई थी। उस समय दंपति वैष्णो देवी की यात्रा पर गए हुए थे। 9 फरवरी को जब परिवार वापस लौटा तो घर का ताला टूटा मिला। घर के भीतर सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी से नकदी तथा सोने के आभूषण गायब थे। जांच में सामने आया कि चोर घर से करीब 25 लाख रुपए के सोने के जेवर और 35 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए थे। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने आसपास लगे निगरानी कैमरों की जांच की तो उसमें तीन से अधिक युवक संदिग्ध रूप से दिखाई दिए। पड़ताल के दौरान महिला के जेठ का बेटा रोहित उर्फ गोलू और उसके कुछ साथियों के नाम सामने आए। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

जमानत के बाद बढ़ा विवाद- पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 19 मई 2026 की दोपहर करीब चार बजे रोहित उर्फ गोलू अपने साथी प्रदुम्न के साथ उसके घर पहुंचा। आरोप है कि दोनों ने पहले दर्ज कराए गए चोरी के मामले में अदालत में बयान बदलने का दबाव बनाया। महिला ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके और उसके पति के साथ अभद्र व्यवहार किया। पीड़िता का आरोप है कि दोनों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। घटना से घबराई महिला तुरंत थाने पहुंची और पूरी जानकारी पुलिस को दी।

चोरी के बाद रिश्ते टूटे- पुलिस के अनुसार चोरी के मामले में जेल जाने के बाद आरोपी जमानत पर बाहर आ चुके हैं। वारदात के बाद पीड़ित परिवार ने आरोपियों और उनके परिवार से संबंध समाप्त कर लिए थे। इसके बावजूद आरोपी लगातार समझौते और बयान बदलने का दबाव बना रहे थे। मामले को लेकर बाणगंगा पुलिस का कहना है कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आरोपियों ने दबाव बनाने के लिए पहले भी किसी तरह की धमकी दी थी या नहीं।

परिवार में हुई वारदात से हैरानी- इस पूरे मामले ने इसलिए भी लोगों को चौंकाया है क्योंकि चोरी की वारदात में पीड़िता के ही रिश्तेदार का नाम सामने आया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पारिवारिक संबंधों के बावजूद जिस तरह बड़ी रकम और आभूषण चोरी किए गए, उससे यह मामला और गंभीर हो गया है।

लसूडिया में गैंगवार का तांडव, कार पर अंधाधुंध फायरिंग, एक की मौत

फायरिंग से अफरा-तफरी मची, लोग दहशत में भागने लगे

इंदौर। इंदौर में देर रात लसूड़िया थाना क्षेत्र के गुलाब कॉलोनी में स्थित एक पेट्रोल पम्प के पास ठेकेदार अभेंद्र सिंह तोमर की चार गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बाइक सवारों ने पूरी प्लानिंग के जरिए हत्या को अंजाम दिया। अभेंद्र भिंड का रहने वाला है और इंदौर में कॉन्ट्रैक्ट था। बीती रात गैंगवार और पुरानी रंजिश ने एक बार फिर खौफनाक रूप ले लिया। गुलाब बाग कॉलोनी के पास रिंग रोड पर 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने एक चलती कार को घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में कार सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी दो बाइक पर सवार होकर आए थे। उन्होंने पहले रेकी की और फिर गुलाब बाग के पास कार को ओवरटेक कर रास्ता रोक लिया। इसके बाद बेहद करीब से कई राउंड गोलियां चलाई गईं। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में घरों-दुकानों की ओर भागने लगे। प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह भिंड में पुरानी रंजिश बताई जा रही है।

डीएवीवी हॉस्टल हंगामे में 18 छात्र चिन्हित, सभी को एक साथ नोटिस

अर्धनग्न नाचने और तोड़फोड़ करने वाले छात्रों पर कार्रवाई

इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के आईईटी विभाग के छात्रावास में हुए हंगामे के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। छात्रावास में अर्धनग्न होकर नाचने और जमकर तोड़फोड़ करने वाले 18 छात्रों की पहचान कर ली गई है, जबकि अन्य छात्रों की पहचान की प्रक्रिया अभी जारी है। सभी छात्रों की पहचान पूरी होने के बाद एक साथ नोटिस जारी किए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने फाइनल ईयर के छात्रों को अंतिम परीक्षा में शामिल होने से भी फिलहाल रोक दिया है। जांच पूरी होने के बाद ही उनके परीक्षा में बैठने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। कुछ दिन पहले आईईटी के रामानुजन बालक छात्रावास-बी में अंतिम वर्ष के छात्रों ने देर रात जमकर हंगामा किया था। छात्रों ने अर्धनग्न होकर 'दारू बदनाम कर दी' गीत पर नृत्य किया और उसके बाद छात्रावास की कुर्सियां, मेज, खिड़कियों के कांच और यहां तक कि प्लास्टिक की पानी की टंकी तक तोड़ दी थी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया था, जो सामाजिक माध्यमों पर तेजी से फैल गया। वीडियो सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद प्रबंधन तत्काल सक्रिय हो गया।

समिति की आपात बैठक

घटना के बाद विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति ने रविवार शाम आपात बैठक बुलाई। बैठक में छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की गई। समिति ने प्रत्येक दोषी छात्र पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाने, अंतिम परीक्षा में शामिल होने से रोकने और परीक्षा परिणाम रोकने जैसे कदमों पर सहमति दी। अब इस अनुशंसा पर अंतिम निर्णय कुलगुरु राकेश सिंघई की अनुमति के बाद लागू किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि कुलगुरु को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है और जल्द ही आवश्यक स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाएगी।

तोड़फोड़ करने पर कार्रवाई

आईईटी के संचालक प्रतोष बंसल ने बताया कि अब तक 18 छात्रों की पहचान की जा चुकी है। बाकी छात्रों की भी पहचान की जा रही है, क्योंकि वीडियो में बड़ी संख्या में छात्र दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई केवल उन छात्रों पर की जाएगी, जिन्होंने छात्रावास में तोड़फोड़ की है। उन्होंने बताया कि छात्रावास में लगभग 150 छात्र रहते हैं। वीडियो की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि किसी निर्दोष छात्र पर कार्रवाई न हो। पूरे मामले में दो से तीन दिन और लग सकते हैं।

अभिभावक नहीं पहुंचे

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार घटना सामने आने के बाद अभी तक किसी भी छात्र के अभिभावक प्रबंधन से मिलने नहीं पहुंचे हैं। प्रशासन का कहना है कि छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी तरह जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। घटना के बाद छात्रावास की व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर भी विश्वविद्यालय प्रशासन सतर्क हो गया है। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की घटनाओं से विश्वविद्यालय की छवि प्रभावित होती है, इसलिए दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाना जरूरी है।

संपादकीय

नॉर्वे की पत्रकार के सवाल पर बवाल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हाल में अपने यूरोप दौरे के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब न देने को सोशल मीडिया में खासा लेकिन अनावश्यक बवाल मचा है। मोदी की नजर में अपने नंबर बढ़वाने के चक्कर में भाजपा समर्थक एक वरिष्ठ पत्रकार ने तो नॉर्वे में पीएम मोदी से एक तीखा सवाल कर उन्हें असहज किया। हालांकि मोदी ने अपनी आदत के अनुसार उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गए, लेकिन पीएम के इसी रवैए और उस महिला पत्रकार की बहादुरी को लेकर सोशल मीडिया में जिस तरह से ओछे कमेंट किए जा रहे हैं, वह अनावश्यक और काफी हद तक अस्वीकार्य हैं। यहां दो बातें हैं। पहला तो मोदी 12 सालों से देश के पीएम हैं, लेकिन वो मीडिया के सीधे सवालों से बचते रहे हैं। हालांकि मीडिया को ज्ञान उन्हें देना होता है, वो देते रहते हैं। कोई राष्ट्राध्यक्ष मीडिया से सीधे बात करे, न करे, कितनी करे, यह उसका अपना निजी निर्णय है। हालांकि माना यह जाता है कि मीडिया जो सवाल करता है, वो अमूमन उस मूक जनता के मन में उठने वाले प्रश्न होते हैं, जो वीवीआईपी सुरक्षा में रहने वाले राजनेता से नहीं कर पाते अथवा नहीं कर सकते। अगर मीडिया ने ऐसा कोई सवाल पीएम से कर लिया तो कोई गुनाह नहीं किया। किए गए प्रश्न का जवाब देना न देना सम्बंधित व्यक्ति पर निर्भर है। मोदी अपवादस्वरूप ही मीडिया से सीधे बात करते हैं और उसमें भी उनका जोर अपनी ही बात कहने पर रहता है। मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान वहां के प्रधानमंत्री जोनस गार स्टोरे के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान नॉर्वे की एक महिला पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी से मीडिया के सवालों का जवाब देने का आग्रह किया था। हेला ने पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवाल क्यों नहीं लेते? क्या आप हमारी सरकार के विश्वास के योग्य हैं? पीएम मोदी ने इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया था। इस पर भारत में भी बहस शुरू हो गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया और पूछा कि सवालों से घबरा क्यों रहे हैं? हेला लेंग ने विदेश मंत्रालय की ब्रीफ़िंग में भी मानवाधिकारों को लेकर सवाल उठाए। इस पर विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत एक सिवलाइज़ेशनल नेशन है। इस घटनाक्रम के बाद जहां भारत में हेला लिंग के बचाव में अभियान शुरू हो गया वहीं दूसरे खेमे में हेला पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए। हिंदी के एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपने नंबर बढ़वाने की नीयत से एक बेहद घटिया पोस्ट फेसबुक पर पोस्ट की। जिसमें पत्रकार हेला बिकीनी में नहा रही है। उसके साथ कैप्शन था कि मोदी से सवाल करने वाली महिला का असली चरित्र। यह निहायत ओछी प्रतिक्रिया थी। किसी महिला का बिकीनी में नहाना उसके चरित्र का परिचायक कैसे हो गया? हेला ने पत्रकार के रूप में सवाल पूछकर कर्तव्य निभाया। मोदी को जवाब नहीं देना था, इसलिए वो सवाल सुनकर आगे बढ़ गए। इस पूरे घटनाक्रम को अनावश्यक तूल देकर नरेटिव बनाना अपने आप में घटिया और कुंठित मानसिकता का परिचायक है। वरिष्ठ भारतीय पत्रकार वर्गीज़ के जॉर्ज ने एक्स पर सही लिखा कि यह मान लेना कि नॉर्वे लोकतंत्र या पत्रकारिता का कोई अंतिम मानक है तो यह अलग-अलग देशों की विशिष्ट परिस्थितियों की अनदेखी करना होगा। पश्चिम में अमेरिका में राष्ट्राध्यक्षों दवारा मीडिया से बात करने को स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। लेकिन भारत में यह परिभाषा नेताओं को मान्य नहीं है। उन्हें जबरन मनवाया भी नहीं जा सकता।

नजरिया

डॉ. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफेसर हैं।

दिखावे की संस्कृति से नाखुश लोग

इस देश में दिखावे की संस्कृति से सच में अब भारतीय जनमानस परेशां है। दुखी है। असहज सा है। हमारे देश में ऐसी बातें केवल खुश करने के लिए की जाती रही है। खुश करने के लिए किसी भी तरह का जोखिम आखिर लोग उठा ही क्यों रहे हैं, समझ में नहीं आता। देश की मूल समस्या का इस प्रकार मज़ाक बन जाता है और जो देश की लीडरशिप की ओर से अपील होती है वह भी हलके में ली जाने लगती है। ऐसे समय में तो चाहिए कि सभी संवेदनशील होकर एक ऐसा सामाजिक ढांचा सशक्त बनाएं जिससे भारत्त की समस्या को हम इंडीजेनस उपलब्धियों से निपटा दें।

देश कठिन दौर से गुज़र रहा है। भारत में इस प्रकार का संकट कभी नहीं आया था, जो आज आ पड़ा है। देश बहुत बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से और अपनी पहचान की दृष्टि से भी लेकिन अब दोनों अपने लिए ऐसे सिंड्रोम की तलाश में हैं जिससे उन्हें अपने अस्तित्व को बचाने में मदद मिले। युद्ध दूसरे देशों में हो रहे हैं लेकिन उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पर पड़ चुका है। एक तरफ पेट्रोल, डीज़ल, गैस की कीमतों की बढ़ोतरी असह्य हो गयी है तो दूसरी ओर इसकी वजह से जो दूसरे सामान महंगे होते जा रहे हैं उसे झेल पाना भारतीय जनमानस के बस की बात नहीं है, ऐसा लगने लगा है। भारत के प्रधानमंत्री ने अपील की है कि देश के लोग सोना न खरीदें, यात्राओं में खर्च न करें। इलेक्ट्रिक सवारियों का उपयोग करें। इससे लोगों में रोष नहीं। इसे लोग स्वीकार भी कर लिए लेकिन इससे ज्यादा रोष उन्हें इस बात से है कि विधायक, मंत्री, मुख्य मंत्री दिखावा करते नज़र आए।

इस देश में दिखावे की संस्कृति से सच में अब भारतीय जनमानस परेशां है। दुखी है। असहज सा है। हमारे देश में ऐसी बातें केवल खुश करने के लिए की जाती रही है। खुश करने के लिए किसी भी तरह का जोखिम आखिर लोग उठा ही क्यों रहे हैं, समझ में नहीं आता। देश की मूल समस्या का इस प्रकार मज़ाक बन जाता है और जो देश की लीडरशिप की ओर से अपील होती है वह भी हलके में ली जाने लगती है। ऐसे समय में तो चाहिए कि सभी संवेदनशील होकर एक ऐसा सामाजिक ढांचा सशक्त बनाएं जिससे भारत्त की समस्या को हम इंडीजेनस उपलब्धियों से निपटा दें। आजकल हमारे विश्वविद्यालय के मेस में बड़े चूल्हे पर लकड़ी से बहुत सी सामग्रियां तैयार हो रही हैं। इसके पहले गैस से ही ब्रेड पकौड़े, चाय, दोपहर का लंच और शाम का डिनर तैयार होता था। जब से गैस मेस चलाने वालों को नहीं मिल रही है वे चूल्हे की व्यवस्था करके लकड़ी से खाना पका रहे हैं। खाना उसी मात्र में तैयार हो रहा है। कुछ अच्छा खाना बन रहा है और लोग अच्छा खा रहे हैं वरना गैस के चूल्हे पर सेंकी हुई रोटियां बनती थीं और उसे ही लोग खाते थे। गैस चूल्हे पर सिंकी हुई रोटियों से जो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहे थे हो सकता है, वे अब कम हो जाएँ क्योंकि चूल्हे पर लकड़ी से सिकी हुई रोटियों की खुशबू और स्वाद पूरे भारत की अपनी सभ्यता में पहले से स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा था फिर आज कैसे न होगा?

देश के विविध विश्वविद्यालयों में इस दौरान मेरा भ्रमण जारी रहा है। अच्छे संस्थाओं में भी अब मेस लकड़ी के सहारे जो चलना शुरू हुए हैं, वे कभी न होते लेकिन आज अधिकांश जगह इसी माध्यम से भोजन तैयार हो रहे हैं। मिड डे मील में ज़रूर प्राइमरी में की आंगनवाड़ी कार्यकत्री और भोजन के लिए रखे गए डेलीवेज के लोग लकड़ियों पर खाना पकाते थे। अब यह विश्वविद्यालयों में हो रहा है। अब हमारी आज की पीढ़ी यह अब समझ पा रही है कि आपातकाल से हम कैसे निपटेंगे। ऊर्जा का संकट देश में अभी डीजल-पेट्रोल व गैस से के संकट की अपेक्षा बहुत मामूली माना जा रहा है लेकिन आने वाले समय में ऊर्जा का संकट भी पूरे विश्व को झेलना है। पूरे विश्व को अँधेरे का भय आज हो न हो लेकिन एक दिन हो सकता है कि यह सबसे बड़ा भय बन जाए।

इसलिए आज की आबादी जो कल की समस्या के लिए तैयार नहीं है, उसे तैयार होना होगा।

भारत के बठिंडा शहर में इन्डेकशन चूल्हा ऑनलाइन या दुकानों पर पिछले महीने मिलना बंद हो गया। गैस की समस्या आने पर लोग इस चूल्हे को खोजते रहे, नहीं मिला। यही हालत भारत के अनेक शहरों की भी होगी लेकिन इसको लेकर लोग कुछ कह न सके। चूल्हे नहीं मिले और गैस न मिलने पर शहर खाली हो गए। जो प्रवासी मजदूर थे वे अपने-अपने घरों की ओर परिवार सहित फिर जाने लगे। सोचिये आज जो एसी, कूलर, फ्रिज, मोबाइल, कम्प्यूटर और हॉस्पिटल में उपयोग में आने वाली विभिन्न जांच मशीने ऊर्जा के अभाव में बंद हो जाएँगी और अँधेरे में हम सन डूबेंगे तो इस पूरी पृथ्वी का क्या होगा? और यह होना ही है क्योंकि हम उपभोगवादी संस्कृति की ओर पिछले कई वर्षों से निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। अँधेरे में ऑक्सीजन नहीं होगा। फिर क्या होगा। यह एक भयावह समय होगा। इस समय के बारे में आज का युवा कोई चिंता नहीं कर रहा है। वह न पेड़ लगाने में दिलचस्पी रखता है और न ही पेड़ बचाने में। जंगल साफ़ हो गए। बाग़-बगीचे कट गए हैं। हमारे गाँव के आसपास आज से 10 वर्ष पहले जो पेड़ थे वे अब दीखते नहीं। अब वहां कोई कुछ दुकाने दिखती हैं या खेती होने लगी उन जमीनों पर। पहले जिन बागों में हम गाय चराने जाते थे और दोपहर में पेड़ों के नीचे छाँव देखकर बैठते थे। वह विश्राम के लिए सभी पेड़ नदारद हैं। अब न छाँव है और न ठांव। अब केवल दूर तक धूप है। देश के लोग अब देस में अपने पेड़, अपने बगीचे और अपनी देसी औषधियों को नहीं खोज सकते, ऐसा भारत बनता गया है। इसलिए लकड़ी व चूल्हे की जो आज की पीढ़ी अनुभव कर रही है वह शायद उन्हें यह सोचने के लिए बाध्य करे कि हमें अपने देश में देसज देस की खोज कायम रखनी चाहिए।

आज हम मानें या न माने लेकिन सचाई यही है कि वर्तमान में पृथ्वी तिहरे संकट जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान का सामना कर रही है। मानवीय गतिविधियों और अनियोजित विकास के कारण पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन बुरी तरह बिगड़ गया है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न योजनाओं में हाल ही में एक अहम रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें डिजिटल महामारी ज़िक्र किया गया है। इस रिपोर्ट का नाम है व्हेन डिजिटल सिस्टम फेल। इस प्रकार के पेंडमिक एक तरफ और दूसरी ओर इंडीजेनस अज्ञानता, इससे हमारा आने वाला समय सुरक्षित तो आज नहीं महसूस हो रहा है। आदिवासी इलाके में आज भी पेट्रोल, गैस या डीजल की कीमतों से फर्क पड़ने वाला नहीं है लेकिन अपने को मुख्यधारा का हिस्सा समझने वाला समाज तो अब ऐसा लगता है कि बिना इसकी उपलब्धता के रह ही नहीं सकता। बिना बिजली की उपलब्धता के वह जी नहीं सकता। इससे कई मोर्चे पर आज की पीढ़ी को लड़ाई लड़नी है, यह तो समझ लेना होगा। यह भी मानकर चलना होगा कि इससे भी बड़े संकट हमारे सामने आने वाले हैं और उसके लिए हमें तैयार रहना होगा।

दिखावे की जगह सच में जीना और सच के अपील करना इसलिए आज ज़रूरी हो गया है। अपने देश के कठिन दौर को हम महसूस करें यह ठीक है लेकिन इसके लिए केवल हमें प्रश्न करने की अनुमति तो नहीं है और न ही कोसने की अनुमति है। हरहाल में खुशहाल जीने की कोशिश में देश निदान की ओर बढ़ते हैं। समाधान ढूंढते हैं। भारत में आज क्या हो रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है। दिखावे की संस्कृति से नाखुश भारतीयों के बारे में आज कोई सोचने को क्यों तैयार नहीं है? इसलिए आवश्यकता यह है कि हम भविष्य की थोड़ी सी चिंता सच में कर लें और उस समाधान की ओर बढ़ें जिसमें भारत की खुशी है। भारत की खुशी की खोज ज़रूरी है वरना अंधकार तो हमें ढंक ही लेंगे।

विचार

प्रो.संजय द्विवेदी

लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार वि वि, भोपाल में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष हैं।

भारतीय मीडिया की बड़ी होती दुनिया !

इन दिनों भारत की मीडिया में बंदिशों और लोकतंत्र के सिकुड़ते जाने की कथाएं हवा में तैर रही हैं। लोकतंत्र बचाने में वे सब आगे हैं जिनके शासन की कथाएं उन्हें खुद मुंह चिढ़ा रही हैं। मीडिया को दबाने, नियंत्रित करने की कहानियां आज की नहीं हैं। लेकिन मीडिया की हिम्मत भी आज की नहीं है। हमारे देश में पत्रकारिता की शुरुआत ही जेम्स आगस्टस हिकी की क्रांतिकारी लेखनी से प्रारंभ होती है, जिसने अंग्रेज लाट साहबों की बैंड बजा दी। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध फूंककर उसने अंग्रेज होकर भी जेलें झेलीं, जुर्माने चुकाए और खामोश मौत पाई। किंतु हिकी यह बता गया कि पत्रकारिता क्यों और कैसे करनी है। इसके बाद आजादी के आंदोलन में यही पत्रकारिता 'खबर' की जगह 'पैगाम' देने वाली बन गयी। जिसके कारण शायर को कहना पड़ा कि जब तोप मुकाबिल तो अखबार निकालो।

सुनने और देखने का समय हमारे देश के हर क्रांतिकारी और आजादी के नायकों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पत्रकारिता को एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया। लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, सुभाषचंद्र बोस, महात्मा गांधी, माधवराव सप्रे, गणेशशंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी सबने पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्र को जागृत किया। पत्रकारिता की भावभूमि आजादी के आंदोलन ने तय कर दी। वह थी जनपक्षधरता, न्याय के लिए संघर्ष और सत्यान्वेषण। आजादी के बाद देश के नवनिर्माण का काम हो या आपातकाल विरोधी संघर्ष हमारे पत्रकारों ने हर जगह अपने उजले पदचिन्ह छोड़े। आज मीडिया का स्वरूप बहुत व्यापक हो गया है। वह अनेक मंचों से की जा रही है। प्रिंट, टीवी, रेडियो से अलग मोबाइल पर हो रही पत्रकारिता गजब कर रही है। कहा जा रहा कि डिजिटल का सूरज कभी नहीं डूबता। इसलिए आप देखें तो पाएंगे मीडिया की पहुंच मोबाइल के माध्यम से ज्यादातर लोगों तक हो रही है। मीडिया कन्वर्जेंस का माध्यम मोबाइल बने हैं। ऐसे में ज्यादातर चीजें सुनी और देखी जा रही हैं। पठनीयता के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। फिर भी इतना बड़ा देश अगर कुछ प्रतिशत में भी पढ़ता है तो भी संख्या आसानी से करोड़ों में होती है। दुनिया के तमाम देश एक भाषा में सोचते, पढ़ते और बोलते हैं। हिंदुस्तान 22 बड़ी भाषाओं और तमाम बोलियों में सुनता, पढ़ता और देखता है। इसलिए भारत के मीडिया का आकार बहुत व्यापक है।

डिजिटल मीडिया ने हमारे माध्यमों को वैश्विक किया है। भारतीय भाषाओं को वैश्विक किया है। कभी फिल्में हमारे भारतीय समाज का वैश्विक चेहरा बनाती थीं। अब मीडिया इसके केंद्र में है। यू-ट्यूब, सोशल मीडिया, वेब माध्यमों, ई-पेपर और ई-बुक्स से एक नई दुनिया बन रही है, जिसने भारत की वैश्विक छवि बनाने का काम किया है। आज भारत और उसकी भाषाओं के साथ अंग्रेजी भाषा में भी भारतीयों की खास उपस्थिति है। वे जो लिख, कह और कर रहे हैं उसने देश को दुनिया में व्यक्त किया है। हिंदुस्तानी जहां-जहां गए अपनी भाषा और संस्कृति के साथ गए और वहां एक लघु भारत खड़ा किया। यह लघु भारत आज मीडिया और संचार माध्यमों से शक्ति पाता है। अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस करता है। एक समय में अपनी भाषा के प्रकाशनों, पत्र-पत्रिकाओं, किताबों और मनोरंजन को प्राप्त करना मुश्किल था, किंतु डिजिटल माध्यमों ने इसे संभव किया है। दूरियां, भूगोल और भाषा सबके अंतर को पाटकर भारत आपके घर पहुंच जाता है। इससे भारत की शक्ति बन रही है। साफ्टपावर क्या कर सकती है, इसे हम सब महसूस कर रहे हैं।

एक नया भारत बनाने और उसके एकीकरण में भारतीय मीडिया की भूमिका को स्वीकार करना चाहिए। अपने प्रारंभ से ही उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम भारतीय पत्रकारिता और साहित्य का स्वर एक रहा है। सबने भारत बोध को स्वर दिया है।

एकत्व को स्थापित किया है। जगदगुरु शंकराचार्य के बाद भारत के एकीकरण का काम पत्रकारिता और साहित्य ने ही किया है। अपने राष्ट्रीय विचारों के समाचार पत्र से तमिलनाडु के सुब्रम्ण्यम भारती जो कर रहे थे, वही काम हिंदी में माखनलाल चतुर्वेदी कर रहे थे। उनके साहित्य और पत्रकारिता दोनों में भारत बोलता है। इस तरह हम देखते हैं कि समाचार माध्यमों ने न सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान किया बल्कि एक देश में एक भाव भी भरा। यही हमारी पत्रकारिता की मूल शक्ति है। पत्रकारिता के नायक लोकमान्य तिलक का वाक्य स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, देश की वाणी बन गया। देश ने आजादी के सपने देखने प्रारंभ किए। उनकी प्रेरणा से अनेक लोग पत्रकारिता में आए और उसी भाव को लेकर आगे बढ़े। इनमें हिंदी के माधवराव सप्रे का उदाहरण सबसे खास है, जिन्होंने तिलक जी के मराठी अखबार 'केसरी' से प्रेरणा लेकर 'हिंदी केसरी' प्रारंभ किया। ऐसे अनेक नायक देश को जोड़ने के सूत्र खोजकर पत्रकारिता के माध्यम से सामने आते रहे। समस्त भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ संपादकों ने इस दौर में जो भाव जागरण किया है, वह अप्रतिम है।

इतनी सारी भाषाओं, बोलियों, खानपान, स्थानीय प्रतीकों को लेकर चलता हुआ देश अगर एक है तो इसका कारण है, उसके सांस्कृतिक प्रवाह का एक होना। लंबी गुलामी, वैचारिक दासता से घिरे बुद्धिजीवियों द्वारा किए लंबे अनर्थ चिंतन के बाद भी इस देश की प्रज्ञा अगर सो नहीं गयी तो इसका कारण इस देश की गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं। समय-समय पर नायक आते रहे हैं। जो हमें याद दिलाते हैं कि सब कुछ कभी खत्म नहीं हो सकता। भारतेंदु हरिश्चंद्र उनमें एक हैं, गांधी हैं, बाद के दिनों में दीनदयाल उपाध्याय, डा. राममनोहर लोहिया, अटलबिहारी वाजपेयी हैं। इनमें से सब पत्रकारिता को अपनी अभिव्यक्ति का केंद्र बनाते हैं। मीडिया के माध्यम से समाज को उसके बोध से जोड़ते हैं। उसी समय समाज को राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त याद दिलाते हैं -

हम कौन थे, क्या हो गये हैं, और क्या होंगे अभी
आओ विचारें आज मिल कर, यह समस्याएं सभी।

जाहिर है हमारी चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई हैं। हमें नित अपने राष्ट्र के समक्ष उपस्थित संकटों के ठोस और वाजिब हल तलाशने हैं। पत्रकारिता, साहित्य और प्रदर्शन कलाओं में यह सामर्थ्य है कि वे समाज को संबल देते हुए उन्हें एकजुट कर सकते हैं। उनको रास्ता दिखा सकते हैं। भारतीय पत्रकारिता कमोबेश अपनी इस भूमिका पर आज भी कायम है। अपनी इस भूमिका को और प्रखर करते हुए पत्रकारिता जगत को वह सब करना ही होगा, जो अपेक्षित है। इसकी कसौटी भी तय है- जनपक्ष और सत्यान्वेषण। इसी में भारतीय पत्रकारिता की मुक्ति है, इसी में उसका गौरव है।

भारत की सामूहिक शक्ति का प्रयोग मॉडल

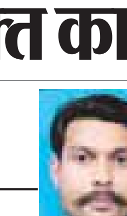

विवेक मिश्रा

वैश्विक अर्थव्यवस्था को दलदल में घसीट रहे, पश्चिम एशिया के संघर्ष से, भारत जैसे प्रगतिशील देश अछूते रह सकें, यह संभव नहीं है, । ऊर्जा की नश्वर तैलीय तमन्नाओं के उन्माद ने तरक्की पसंद मुल्कों की सरल राहों को रोका है। अतिवाद और तेलीकरण के परिवेश में शांति प्रयासों की कोई सुबह होती नहीं दिख रही है, बढ़ती हुई पेट्रोल-डीजल की कीमतें इस वास्तविकता की पुष्टि कर रहीं हैं ।

ऐसे संकटकाल में प्रधानमंत्री की देशवासियों से उपयोग व उपभोग में संयम बरतने की अपील, धैर्य की सभी कसौटियों को कसने के बाद ही की गई होगी। राजनीतिक दृष्टि से इस अपील की गहन गवेषणा की जा सकती है। परंतु इससे देश की मौजूदा समस्या और इससे जुड़े तथ्यात्मक सत्य, हमारी समीक्षा का इंतजार नहीं करेंगे, इन्हें तात्कालिक समाधान चाहिए। इस एवज में कि हम अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 85% विदेशों से आयात करते हैं,जिसमें फारस की खाड़ी वाले मार्ग का हिस्सा 35% है। चीन के बाद गोल्ड का सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है और यह भी आयात पर ही निर्भर है। इस तरह ईंधन और स्वर्ण आभूषण से दबी भारतीय अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा डॉलर पर बहुत निर्भर करती है, जंग से निर्मित हालातों में बढ़ती कीमतों और हमारी मांगों से विदेशी मुद्रा भंडार के तेजी से कम होने का खतरा बढ़ रहा है,जनवरी की तुलना में मई 2026 में यह लगभग 723 बिलियन डॉलर से 690 बिलियन डॉलर पर आ चुका है।

इन परिस्थितियों में संयम के संयुक्त प्रयत्नों से ही हम भारत के प्रगति पथ को निर्बाध संचालित रख सकते हैं। संयुक्त प्रयास इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हम 140 करोड़ भारतीयों के दैनंदिन व्यवहार और बरतने की आदतों से जुड़ा विषय है। प्रयासों के इस क्रम में नेतृत्व कर्ताओं द्वारा अपने काफिलों से कमोबेश पचास प्रतिशत वाहन कम करने की बात कही गई है, जिसकी पालना फिलहाल कई माननीयों के द्वारा सड़कों पर किए गए वाहन शक्ति प्रदर्शन में देखने को नहीं मिल सकी , हालांकि केंद्रीय व शीर्ष नेतृत्व सराहनीय रूप से प्रयास कर रहे हैं। निजी क्षेत्र जरूर अपने सशक्त तकनीकी ढांचे के दम पर वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्था को तुरंत मूर्तरूप दे सकते हैं। सरकारी कार्यालयों में भी अधिकारियों - कर्मचारियों के आवागमन को सार्वजनिक व साझा परिवहन से जोड़कर इच्छित परिणाम हासिल किए जा सकते है। अधिकांशतः सभी सरकारी दफ्तर सप्ताह में पांच दिन संचालित किए जाते हैं, लेकिन देशभर में स्कूल प्रायः सप्ताह में छह दिन लगाए जा रहे हैं । ग्रीष्मकालीन अवकाशों की अवधि भी 1980 से 2010 तक 2 माह तक हुआ करती थी , यह अधिकांश राज्यों में अब 30 से 45 दिन तक सिमट चुकी है। आने वाले 1 वर्ष के लिए यदि 5 दिवसीय व्यवस्था और ग्रीष्मकालीन अवकाश को बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है, तो कुछ चमत्कारी परिणाम हासिल हो सकते है।

इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के हिसाब से देशभर के 10 लाख सरकारी स्कूलों में 51 लाख सरकारी शिक्षक कार्यरत हैं। यदि यह सभी शिक्षक बाइक साझा कर अपने अपने घरों से स्कूल आने-जाने के लिए कम से कम 10 किलोमीटर का सफर भी तय करते हैं, तो एक मोटरसाइकिल से दो शिक्षकों को 200 एम.एल. पेट्रोल की जरूरत होती है। वहीं देशभर के शिक्षकों के साथ ईंधन की यह खपत 510000 लीटर /प्रतिदिन हो जाती है। पेट्रोल की इस खपत को यदि अगले एक वर्ष के लिए फाइव डे वर्किंग मॉडल और 2 महीने के ग्रीष्मकालीन अवकाश से जोड़ दें (मौजूदा 1 माह के अवकाश से 30 दिन अधिक) तो कुल 39,780,000 लीटर पेट्रोल की बचत की जा सकती है । इतने मात्रा के पेट्रोल को परिष्कृत करने में लगने वाले कच्चे तेल की तादाद 86,478,261 लीटर या 77,698 मीट्रिक टन हो जाती है। (1 लीटर कच्चे तेल से लगभग 450 एम.अल. पेट्रोल का उत्पादन होता है।) आज अंतरराष्ट्रीय बाजार मीं इसकी कीमत लगभग 478 करोड़ रुपए होगी। हालांकि यह तथ्य भी स्पष्ट करना जरूरी है, कि भारत में कच्चे तेल की प्रतिदिन खपत 7,50,000 मीट्रिक टन है,अर्थात वर्षभर किए गए इन तमाम प्रयासों के बाद भी हम एक दिन की खपत का केवल 10% प्रतिशत ही कच्चा तेल बचा सकेंगे, जो देश में मात्र ढाई घंटे की आपूर्ति को पूरा करेगा। प्रथम दृष्टया इस प्रयोग का सीमित प्रभाव क्षेत्र हमें हताशा से भर सकता है, किंतु यह ध्यान रखना होगा कि यह 51 लाख सरकारी शिक्षकों के साथ किया गया प्रयोग है और यह भारत की कुल जनसंख्या का मात्र 0.36% प्रतिशत है। इस मॉडल को स्कूलों में पढ़ने वाले 25 करोड़ विद्यार्थियों की संख्या के अनुपालन से और प्रधानमंत्री के 140 करोड़ भारतीयों से किए गए आग्रह के अनुशासन से जोड़ दिया जाए, तो अगले एक वर्ष में जो परिणाम हम हासिल करेंगे, वह प्रत्येक भारतीय को राष्ट्रभावना के अप्रतिम रोमांच से भर देगा। यही नहीं, इस प्रयोग में की गई कुल खपत में 77,698 मीट्रिक टन की कमी का अर्थ है, पर्यावरण में 2 लाख 40 हजार मीट्रिक टन के कार्बन फुटप्रिंट को घटाना , यह 57 हजार पेट्रोल कारों द्वारा पूरे एक साल में किए गए कुल प्रदूषण को कम कर देना है।

इसी तर्ज पर भौतिक रूप से गोल्ड की खरीद पर नियंत्रण रख, मांगलिक कार्यों में उतने ही मूल्य से ईटीएफ, एफडी आदि में निवेश कर , एक ही छत के नीचे जलते अलग अलग चूल्हों को एक-कर , हम विश्व को अपने सामर्थ्य का परिचय दे सकते हैं। हॉर्मूज के इस संकट का निराकरण सरकारी नीतियों से कहीं अधिक , देशवासियों की सामूहिक शक्ति में निहित है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.-453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

दृष्टिकोण

आसिम अनमोल

लेखक स्तंभकार हैं।

गर्मी की मिसाइलें छोड़ी जा रहीं आसमान से !

गर्मी फिर आ गई। गर्मी बारिश लू के थपेड़े मानवीयता को चारों दिशाओं में बड़े साहस के साथ घेरे खड़े हैं । जितना गर्मी से लोग परेशान नहीं हो रहे हैं । उतना मौसम विभाग की चेतावनी से भयभीत हो रहे हैं। जिनको गर्मी नहीं लग रही होती , उनको भी लगनी शुरू हो रही है। गर्मी का प्रकोप मानसिक पटल पर खूब उत्पात मचा रहा है । गर्मी और लाइट न जाने किस जनम का बदला ले रहे हैं। इधर गर्मी अपनी आसमानी सत्ता का पावर दिखा रही है। उधर लाइट विधुत विभाग के आकाओं से भीख रुपी अर्जित की जाने वाली लाइट से यदा कदा पंखे व कूलर चलवा रही है। कुछ समय बाद गर्मी यह कहकर चली जा रही है कि तुम आम या खास को ज्यादा गर्माहट मत देना। बस अपने हद में रहकर हल्के फुल्के पसीने छुड़वाते रहना ताकि तुम्हारा संसार में तापमानीय भरम बना रहे। वरना तुम्हारी प्रतिष्ठा पर बन आएगी। मौसम विभाग , लाइट और गर्मी तीनों की तिकड़ी गर्मी का शुभारम्भ करते हुए इंसानी शरीर को पसीना पसीना करके चिपचिपा बनाने पर तुली हुई है। मौसम विभाग शरीर के चिपचिपेपन में बृद्धि करते हुए गर्मी के बढ़ने की ओर पुरज़ोर तरीके से इशारा कर रहा है। छोटे शहरों में लाइट यह कहकर आ जा रही है कि अपना अपना पसीना बोतलों में भरकर रखिए। मैं रोस्टिंग निपटा के आती हूँ। यह तीनों ही अनुमानित ढंग से ऐसे अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे सरकार अपने मुताबिक काम करती है। अब भला गर्मी को सोचना चाहिए कि इंसान का डी.एन.ए.पहले से ही जीवन की समस्याओं और उलझनों में उलझा हुआ है। ऊपर से तुम हर साल सताने आ जाती हो। डिग्री सेल्सियस रुतबा अलग दिखाती रहती है। घटने का काम ही नहीं लेती है। उसको लगता है की घटने पर मेरा अपमान हो जाएगा। इस लिए वीर तुम बड़े चलो की तर्ज़ पर गर्मी बढ़ती ही रहती है। इसी कारण सरकारी ऑफिस दोपहर में सोने और लेटने के विश्रामगृह बनते जा रहे हैं। घर घर नींद पसर रही है। गर्मी की पहुंच भी सीधे गगन तक है। इस लिए इंसान का मानसिक पारा इतना गरम कर रही है कि घरेलू माहौल में भी रोज़ रोज़ की कलह पैदा कर देती है। यानी गर्मी लड़ाई झगड़ा करवाने की भी प्रतीक है। अब अगर इंसान अपनी गर्मी की हैसियत दिखाने की ओर अग्रसर होगा तो गर्मी पूरे व्यक्तितत्व को जलाने का ही काम करेगी। गर्मी का मिज़ाज़ समझने की ज़रुरत होनी चाहिए। उसके मिज़ाज़ के लिहाज़ से अपना मानसिक संतुलन बनाकर रखना चाहिए। अब प्राकर्तिक गर्मी यह तो नहीं कहती कि आप अपने सिर के बाल नोचते घूमे। बीवी पर गर्मी का गुस्सा उतारें । पड़ोसियों के बच्चों की आपस में कोई नोक झोंक हो जाए तो खुद परिपक्व बनकर लड़ाई झगड़ों के प्रतीक होते घूमें। बाप की अच्छी सलाह पर जिस्म से बहते पसीने से आजिज़ आकर बाप के साथ खराब सुलूख की अंताक्षरी खेलें। दुनियाँ को अपनी गर्मी से इतना गर्म न करें कि दुनियाँ आपकी आलोचनाओं भरी बातों को जगह जगह चाय पानी की तरह परोसती घूमें। ऐसे ही एक रोज़ पत्नी पति से बोली एक ठंडा ठंडा कूल कूल पाउडर का डिब्बा लाकर दीजिए। पति बोला पिछले सप्ताह तो लाकर दिया था। पाउडर लगाती हो या पडोसी को दान कर देती हो। पत्नी तिलमिलाती हुई बोली मुझ पर क्यों भड़क रहे हो। पाउडर त्वचा पर लगाती हूँ टिकता ही नहीं। भड़कना ही है तो बिजली बालों और उस विधाता पर भड्कों जो आसमान से गर्मी की मिसाइलें चलाकर संसार के प्रत्येक दिमाग़ को गर्मागर्म कर रहा है।

भारतीय कृषि का नया रोडमैप

निलेश देसाई

लेखक कृषि मामलों के जानकार हैं।

दाम, पानी और गारंटीड खरीद का त्रिआयामी सुरक्षा कवच

यह घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन नीतिगत दृष्टिकोण से इसकी टाइमिंग एक बड़े विरोधाभास को रेखांकित करती है। जिस दिन यह ऐलान हुआ, उसी दिन उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 48.2 डिग्री तक पहुँच गया था, जिसने इसे देश के अत्यंत गर्म स्थानों में शामिल कर दिया। इसी दौरान विश्व के सबसे गर्म शहरों की सूचियों में भारत के शहरों का बड़ा प्रभुत्व उभरकर आया है। यह जमीनी हकीकत एक बुनियादी सवाल खड़ा करती है: जब चरम मौसम के कारण खेत ही भट्ठी बन जाएं, तो केवल कागजी मूल्य किसान को कितनी सुरक्षा दे पाएगा?

खरीफ 2026-27 के एमएसपी ऐलान के बीच बांदा 48.2 डिग्री सेल्सियस पर झुलसा; 51 साल की स्टडी बोली–बाजरा सबसे वल्नरेबल, अब सिर्फ दाम नहीं, 'सिंचाई और खरीद सुरक्षा' का समय। केंद्र सरकार ने खरीफ 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का ऐलान कर दिया है। बाजरे का एमएसपी 125 रुपए बढ़कर 2,900 प्रति क्विंटल, धान 2,441, मक्का 2,560 और अरहर 8,000 प्रति क्विंटल तय हुआ है। सरकार का आकलन है कि इससे लागत पर 50 से 75 प्रतिशत तक का लाभ मिलेगा–विशेषकर बाजरे में लगभग 56 प्रतिशत और रागी में 75 प्रतिशत तक का रिटर्न बताया गया है।

यह घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन नीतिगत दृष्टिकोण से इसकी टाइमिंग एक बड़े विरोधाभास को रेखांकित करती है। जिस दिन यह ऐलान हुआ, उसी दिन उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 48.2 डिग्री तक पहुँच गया था, जिसने इसे देश के अत्यंत गर्म स्थानों में शामिल कर दिया। इसी दौरान विश्व के सबसे गर्म शहरों की सूचियों में भारत के शहरों का बड़ा प्रभुत्व उभरकर आया है। यह जमीनी हकीकत एक बुनियादी सवाल खड़ा करती है: जब चरम मौसम के कारण खेत ही भट्ठी बन जाएं, तो केवल कागजी मूल्य किसान को कितनी सुरक्षा दे पाएगा?

दाम का सच: लागत का अधूरा आकलन

वर्तमान में सरकार ए2+एफएल फॉर्मूले पर एमएसपी तय करती है–यानी केवल नकद खर्च और पारिवारिक मजदूरी। इस आधार पर बाजरे की लागत 1,860 रुपए मानकर 2,900 रुपए का मूल्य तय किया गया है।

परंतु, व्यावहारिक कृषि अर्थशास्त्र और एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, मूल्य निर्धारण सी 2 फॉर्मूला (जमीन का काल्पनिक किराया + लगाई गई पूंजी पर ब्याज) के आधार पर होना चाहिए। यदि सी 2+50 प्रतिशत सूत्र को लागू किया जाए, तो धान का एमएसपी 2,441रुपए की जगह लगभग 3,200 रुपए होना चाहिए था। पिछले एक दशक में डीजल (लगभग 78 प्रतिशत वृद्धि) और डीएपी (लगभग 90 प्रतिशत वृद्धि) जैसी इनपुट लागतों में आया उछाल देखते हुए, वर्तमान मूल्य वृद्धि किसानों की वास्तविक आर्थिक सुरक्षा के लिए अपर्याप्त महसूस होती है।

पानी का संकट: भट्ठी बनते खेतों में उत्पादन की चुनौती

51 साल के ऐतिहासिक डेटा और 563 जिलों पर आधारित हालिया 'क्रॉप रिस्क असेसमेंट-क्लाइमेट स्टडी' ने हमारी पारंपरिक प्राथमिकताओं को झकझोर दिया है। इस अध्ययन के अनुसार, तापमान में महज 1 डिग्री सेल्सिसयम की वृद्धि होने पर बाजरे की पैदावार में लगभग 19.1 प्रतिशत की गिरावट हो सकती है; कुछ शुष्क जिलों में यह नुकसान 38.5 प्रतिशत तक पहुँच जाता है।

गेहूं (-5.4 प्रतिशत) और चावल (-7.1 प्रतिशत) की तुलना में बाजरा–जिसे हम पारंपरिक रूप से सूखा प्रतिरोधी मानते थे–चरम गर्मी में सबसे अधिक संवेदनशील साबित हो रहा है। इसे बुंदेलखंड या मध्य प्रदेश के झाबुआअलीराजपुर जैसे अर्धशुष्क अंचलों के उदाहरण से समझें, जहाँ तापमान आज 40 डिग्री सेल्सिसयस से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बाजरे के लिए आदर्श तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तापमान में इस भारी वृद्धि के कारण, यदि फसल खेत में ही झुलसकर नष्ट हो जाती है, तो प्रति क्विंटल बढ़ा हुआ दाम बेअसर हो जाता है। किसान की जेब में आय तब पहुँचेगी, जब फसल बाजार तक पहुँचने के लिए बचेगी।

खरीद का अभाव: बाजार में वास्तविक मांग की कमी

नीति आयोग और विभिन्न राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के आंकड़े बताते हैं कि देश के महज लगभग 6 प्रतिशत किसानों को ही एमएसपी का वास्तविक लाभ मिल पाता है। उदाहरण के लिए, बाजरे का राष्ट्रीय एमएसपी भले ही 2,900 रुपए प्रति क्विंटल घोषित हो, लेकिन स्थानीय मंडियों में वास्तविक व्यापार 2,100 से 2,400 रुपए के बीच सिमट जाता है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जैसे क्षेत्रों में, जो भीषण गर्मी की चपेट में हैं, न तो पर्याप्त सरकारी खरीद केंद्र उपलब्ध हैं और ना ही वैज्ञानिक भंडारण (सिलोसिस) की व्यवस्था। दलहन और तिलहन की स्थिति भी इससे अलग नहीं है, जहाँ सरकारी खरीद का स्तर अक्सर एकल अंकों (सिंगल डिजिट) तक ही सिमट जाता है।

त्रिआयामी सुरक्षा कवच: 'एमएसपी 1.0' से 'एमएसपी 2.0' का विजन

इन संरचनात्मक और पर्यावरणीय चुनौतियों के सामने स्पष्ट है कि भारतीय कृषि को अब केवल मूल्य घोषणा (एमएसपी 1.0) के सीमित दायरे से बाहर निकलना होगा। देश की खाद्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए हमें एक त्रिआयामी दृष्टिकोण–'एमएसपी 2.0' (दाम, पानी और गारंटीड खरीद) को कृषि नीति का मुख्य आधार बनाना होगा।

प्रथम कवच: दाम में सुधार (सी2+50 प्रतिशत का वैधानिक ढांचा)

कागजी मुनाफे के स्थान पर वास्तविक वित्तीय सुरक्षा देने के लिए सी 2+50 प्रतिशत फॉर्मूले को मूल्य निर्धारण का वैधानिक आधार बनाया जाए। इसके साथ ही, इनपुट लागतों (डीजल, खाद, बीज) की वास्तविक बाजार महंगाई के अनुपात में प्रतिवर्ष समर्थन मूल्य को गतिशील (डायनामिक) रूप से अपडेट करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे एमएसपी के वार्षिक आंकड़े केवल राजनीतिक घोषणा न होकर वास्तविक लागत सुरक्षा का उपकरण बन सकते हैं।

द्वितीय कवच: पानी और जलवायु सुरक्षा

'क्रॉप रिस्क असेसमेंट- क्लाइमेट स्टडी' में चिन्हित देश के सबसे अधिक जलवायुसंवेदनशील जिलों के किसानों को फसल के जोखिम की भरपाई के लिए घोषित एमएसपी के ऊपर 200 रुपए प्रति क्विंटल का प्रत्यक्ष 'क्लाइमेट बोनस' दिया जाए। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में टपक (ड्रिप) और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों पर 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाए। इसके अलावा, प्रत्येक पंचायत स्तर पर जल पुनर्भरण के लिये खेत तालाबों, चेक डैमों और सघन वृक्षारोपण को अनिवार्य नीतिगत हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि सिंचाई का सुरक्षा तंत्र ही फसलों को चरम तापमान से बचा सकता है।

तृतीय कवच: गारंटीड खरीद और मांग सृजन

मोटे अनाजों (श्री अन्न) और दलहनतिलहन के लिए हर जिले में विकेंद्रीकृत सरकारी खरीद केंद्र स्थापित कर शतशत प्रतिशत भौतिक खरीद की गारंटी दी जाए। इस उत्पादन को खपाने और बाजार में स्थायी मांग पैदा करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), आंगनवाड़ियों और मध्यान्ह भोजन योजना में मोटे अनाजों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। निजी व्यापारियों द्वारा बनाई जाने वाली गुटबाजी को रोकने के लिए बाजार में एक 'फ्लोर प्राइस' का नियामक ढांचा हो, जो मध्य प्रदेश की 'भावांतर भुगतान योजना' के व्यावहारिक दोषों से सीखते हुए किसान के हितों की रक्षा करे। खरीफ फसलों के मूल्यों में वृद्धि एक सकारात्मक और स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह वर्तमान कृषि पारिस्थितिकी संकट का आंशिक समाधान मात्र है। 48 डिग्री सेल्सियस की तपिश में झुलसती भारतीय खेती को केवल ऊंचे आंकड़ों के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। किसान और देश की वास्तविक सुरक्षा तब सुनिश्चित होगी, जब मूल्य सुरक्षा को पानी की उपलब्धता और गारंटीड खरीद के मजबूत धरातल पर टिकाया जाएगा। सरकार को अब 'अखबारों की हेडलाइन' से आगे बढ़कर 'खेत की लाइफलाइन' को मजबूत करने वाले इस त्रिआयामी रोडमैप को अपनाना होगा। तभी हम एक आत्मनिर्भर, टिकाऊ और समृद्ध कृषि भविष्य की नींव रख पाएंगे।

जैव विविधता

जयदेव राठी

लेखक एडवोकेट हैं।

मानव सभ्यता की सांसें बचाने का संघर्ष

हर वर्ष 22 मई को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता के लिए दिन हमें यह याद दिलाता है कि मनुष्य अकेला नहीं है; उसकी सभ्यता, अर्थव्यवस्था, भोजन, जल, औषधि और भविष्य सब कुछ जैव विविधता पर आधारित है। यदि धरती से जंगल, जीव-जंतु, पक्षी, कीट, नदियाँ और वनस्पतियाँ समाप्त होने लगें, तो मानव सभ्यता का अस्तित्व भी लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, सूखा, बाढ़, समुद्री प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रही है। इन सभी संकटों के मूल में कहीं न कहीं जैव विविधता का विनाश जुड़ा हुआ है। दुनिया जितनी तेजी से तकनीकी विकास की ओर बढ़ी है, उतनी ही तेजी से उसने प्रकृति के संतुलन को भी बिगाड़ा है। यही कारण है कि आज 'विकास बनाम प्रकृति' का प्रश्न मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जीवों, वनस्पतियों, सूक्ष्मजीवों और पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता। इसमें जंगल, घास के मैदान, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, जीव-जंतु, पक्षी, कीट और पेड़-पौधे सब शामिल हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो प्रकृति का पूरा जीवंत संसार ही जैव विविधता है। धरती पर हर जीव की अपनी भूमिका होती है। मधुमक्खियाँ परागण करती हैं, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, नदियाँ जीवन को बनाए रखती हैं, जंगल वर्षा चक्र को संतुलित करते हैं और सूक्ष्मजीव मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हैं। यदि इनमें से कोई एक कड़ी भी कमजोर होती है, तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है।

यूनाइटेड नेशन्स ने जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाने की शुरुआत की। इसका उद्देश्य केवल कार्यक्रम आयोजित करना नहीं, बल्कि यह समझ विकसित करना है कि मानव जीवन और प्रकृति एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आज विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आर्थिक विकास की अंधी दौड़ में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, समुद्र प्लास्टिक से भरते जा रहे हैं और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास समाप्त हो रहे हैं। ऐसे समय में यह दिवस प्रकृति के साथ संतुलित विकास की आवश्यकता पर बल देता है।

भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहाँ अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। हिमालय से लेकर पश्चिमी घाट तक, थार रेगिस्तान से लेकर सुंदरबन के मैंग्रोव तक भारत में प्रकृति की अद्भुत विविधता देखने को मिलती है। देश में हजारों प्रकार की वनस्पतियाँ, पक्षी, जीव-जंतु और औषधीय पौधे पाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है। पेड़ों, नदियों, पर्वतों और पशु-पक्षियों को धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व दिया गया। यही कारण था कि भारतीय समाज लंबे समय तक प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलता रहा। पीपल, बरगद, तुलसी, गाय, नाग और नदियों के प्रति सम्मान केवल आस्था नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण का सामाजिक माध्यम भी था। लेकिन आधुनिक जीवनशैली और अंधाधुंध शहरीकरण ने इस संतुलन को कमजोर किया है। आज बड़े-बड़े शहरों के विस्तार ने जंगलों को निगलना शुरू कर दिया है। खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी और जल दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

वनों की अंधाधुंध कटाई जैव विविधता के लिए

सबसे बड़ा संकट बन चुकी है। जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं होते, बल्कि लाखों जीवों का घर होते हैं। जब जंगल कटते हैं, तो असंख्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन भी कई प्रजातियों के लिए संकट पैदा कर रहा है। धरती का बढ़ता तापमान हिमनदों को पिघला रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है। इसका सीधा प्रभाव वन्य जीवों और वनस्पतियों पर पड़ रहा है। प्लास्टिक, रासायनिक कचरा और औद्योगिक प्रदूषण नदियों, समुद्रों और मिट्टी को विषैला बना रहे हैं। समुद्री जीव प्लास्टिक निगलकर मर रहे हैं और कई पक्षियों की प्रजातियाँ तेजी से कम हो रही हैं। कई वन्य जीव केवल अवैध शिकार और तस्करी के कारण विलुप्ति के कगार पर पहुँच चुके हैं। हाथी, गैंडा, बाघ और कई दुर्लभ पक्षी आज भी शिकार माफियाओं के निशाने पर हैं।

बहुत से लोग मानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण विकास में बाधा है, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। कृषि, मत्स्य पालन, पर्यटन, औषधि उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह जैव विविधता पर निर्भर हैं। यदि मधुमक्खियाँ समाप्त हो जाएँ, तो परागण प्रभावित होगा और खाद्य उत्पादन घट जाएगा। यदि जंगल समाप्त होंगे, तो वर्षा चक्र बिगड़ेगा और जल संकट गहरा जाएगा। इसलिए जैव विविधता केवल पर्यावरण का विषय नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता का भी आधार है।

भारत तेजी से शहरीकरण और औद्योगीकरण की दिशा में बढ़ रहा है। यह विकास आवश्यक भी है, लेकिन यदि यह प्रकृति के संतुलन को नष्ट करके होगा, तो भविष्य में गंभीर संकट पैदा होंगे। देश के कई हिस्सों में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। गर्मी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कई शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुँच चुका है। नदियाँ सिकुड़ रही हैं और वन क्षेत्र लगातार दबाव में हैं। यह संकेत बताते हैं कि प्रकृति अब चेतावनी देने लगी है। विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत के कृषि क्षेत्रों में मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। जल स्रोत कम होते जा रहे हैं। यदि समय रहते जैव विविधता संरक्षण पर गंभीर कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ियों को जल, भोजन और स्वच्छ वातावरण के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।

समाधान केवल सरकारी योजनाओं से नहीं निकलेंगे। समाज और आम नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। वृक्षारोपण को केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनआंदोलन बनाना होगा। प्राकृतिक जंगलों को बचाना और स्थानीय प्रजातियों के पेड़ लगाना जरूरी है। रासायनिक खेती की जगह जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा। तालाब, वर्षा जल संचयन और पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन अत्यंत आवश्यक है। एकल उपयोग प्लास्टिक पर सख्त नियंत्रण और वैकल्पिक उत्पादों को बढ़ावा देना समय की मांग है। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों को भी प्रकृति संरक्षण के अभियान से जोड़ना होगा।

आज दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक और औद्योगिक विस्तार की ओर बढ़ रही है। यह प्रगति आवश्यक है, लेकिन यदि तकनीक प्रकृति को नष्ट करने लगे, तो वह विकास नहीं बल्कि विनाश का मार्ग बन जाती है। भविष्य का वास्तविक विकास वही होगा जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के बीच संतुलन स्थापित करे। 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट' केवल अंतरराष्ट्रीय मंचों का शब्द नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व की आवश्यकता बन चुका है। विश्व जैव विविधता दिवस मानवता के आत्ममंथन का अवसर है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या विकास की हमारी वर्तमान दिशा भविष्य को सुरक्षित बना रही है या विनाश की ओर ले जा रही है। प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना संभव नहीं है। यदि जंगल समाप्त होंगे, नदियाँ सूखेंगी, जीव-जंतु विलुप्त होंगे और मिट्टी बंजर होगी, तो आधुनिक तकनीक भी मानव सभ्यता को नहीं बचा पाएगी। इसलिए अब समय आ गया है कि विकास और प्रकृति के बीच संघर्ष नहीं, बल्कि संतुलन स्थापित किया जाए। धरती केवल वर्तमान पीढ़ी की संपत्ति नहीं है; यह आने वाली पीढ़ियों की धरोहर भी है। यदि आज जैव विविधता को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य हमें कभी माफ नहीं करेगा।

सामयिक

डॉ.मुरलीधर चाँदनीवाला

लेखक साहित्यकार हैं।

स्कूली बच्चे बुरी तरह दबाव में हैं

ऐसी शिक्षा किस काम की, जो बच्चों से उनके परिवार के साथ बैठने के मौके ही छीन ले। पढ़ाई का दबाव इतना बढ़ा दिया गया कि बच्चे खेल के मैदान से बहुत दूर होते चले गये हैं। स्कूल और समाज की गतिविधियों में भाग लेने के लिये उनके पास समय ही नहीं होता। मोटी-मोटी फीस लेकर भी स्कूल बच्चों को इस हाल पर छोड़ देते हैं कि उन्हें स्कूल से छूट कर कोचिंग के लिये दौड़ लगानी पड़ती है। नई शिक्षा नीति के पास सर्वांगीण शिक्षा का कोई तो फार्मूला होगा, जो स्कूलों में लागू नहीं हो पाया। जो शिक्षा बच्चों को जीवन के लिये तैयार नहीं करती, क्या वह सचमुच की शिक्षा है भी?

पूरे देश में नई शिक्षा नीति की खूब प्रशंसा हुई। ऐसा माहौल बना दिया गया कि भारतीय शिक्षा सीधे हिमालय की चोटी पर चढ़कर अपना परचम लहरा देगी। पाँच साल से ऊपर हो गये हैं। अभी तक शिक्षा नीति का कोई ऐसा ठोस असर नहीं दिखा, जिससे हमारे बच्चे और अभिभावकों को थोड़ी सी भी राहत मिल सके। ऊपर बैठे हुए लोगों को यह जानने और समझने कि फुर्सत नहीं, कि स्कूली बच्चे बुरी तरह दबाव में हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक तरफ पाठ्यक्रम बहुत जटिल कर दिया है, दूसरी तरफ परीक्षा प्रणाली में लगातार फेरबदल की नीति ने उलझनें बढ़ा दी हैं। प्रायमरी से लेकर हाईस्कूल और हायर सेकंडरी तक के बच्चे घर के एक कमरे में बंद होकर सिर्फ दबाव झेल रहे हैं।

ऐसी शिक्षा किस काम की, जो बच्चों से उनके परिवार के साथ बैठने के मौके ही छीन ले। पढ़ाई का दबाव इतना बढ़ा दिया गया कि बच्चे खेल के मैदान से बहुत दूर होते चले गये हैं। स्कूल और समाज की गतिविधियों में भाग लेने के लिये उनके पास समय ही नहीं होता। मोटी-मोटी फीस लेकर भी स्कूल बच्चों को इस हाल पर छोड़ देते हैं कि उन्हें स्कूल से छूट कर कोचिंग के लिये दौड़ लगानी पड़ती है। नई शिक्षा नीति के पास सर्वांगीण शिक्षा का कोई तो फार्मूला होगा, जो स्कूलों में लागू नहीं हो पाया। जो शिक्षा बच्चों को जीवन के लिये तैयार नहीं करती, क्या वह सचमुच की शिक्षा है भी?

हम कभी यह क्यों नहीं सोचते कि स्कूलों में हमारा भविष्य पल रहा है। जो राष्ट्र भविष्य को उसके हाल पर छोड़ दे, वह लाख दावे करते रहने के बाद भी अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इन दिनों मासूम बच्चों के चेहरे मुरझाये हुए लगते हैं। कभी-कभी लगता है कि वे शिक्षा व्यवस्था के आतंक में जी रहे हैं, और कोई भी उनकी पूरी मदद नहीं कर सकता। पूरे साल उनके माथे पर परीक्षा का भूत सवार रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि आजकल के बच्चे अपने समय से आगे चलने की ताकत रखते हैं, लेकिन हमने उनके पाँवों में बेड़ियाँ बाँध रखी है। देश- विदेश की काल-परिस्थिति पर उन्हें अभिव्यक्त होने देना चाहिए था, लेकिन हमने उन्हें उन मोटी-मोटी किताबों से बाँध दिया, जो एक दिन उनमें ऊब पैदा कर लौट जायेंगी।

बच्चों को कौन-कौन सी भाषा पढ़नी चाहिए, इस बारे में बच्चों से कभी नहीं पूछा जाता। अचानक कहीं से फरमान चला आता है कि अब ये भाषाएँ पढ़नी होंगी, और इस भाषा की परीक्षा के प्राप्तांक नहीं जुड़ेंगे। हर साल इस तरह की बेमतलब की कवायद से हासिल क्या होता है? क्या यह तथ्य गम्भीर नहीं है, कि भारतीय शिक्षा के महत्व को तवज्जो देने वाली सरकार मातृभाषा को उसका उचित सम्मान दिलाने में कामयाब नहीं हो सकी। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को कोई चुनौती मिली आज तक? भारतीय भाषाएँ चाहे जितनी सम्पन्न और गौरवशाली हों, वे स्कूलों में दोयम दर्जे की ही हैं। भारतीय संस्कृति का गुणगान करने वाली सरकार चाहती तो संस्कृत को हाईस्कूल तक अनिवार्य रहने दे सकती थी, लेकिन वह इसे

और पीछे ले गई।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएँ भी अब भरोसे लायक नहीं रहीं। एक राज्य में कठिन से कठिनतर प्रश्नपत्र पहुँचते है, दूसरे राज्य में उतने ही सरल। परीक्षाओं के चलते ही छात्र-अभिभावक परीक्षा व्यवस्था के विरुद्ध लामबंद होने लगते हैं, बाद में बोर्ड को राहत देने वाले समझौते करने पड़ते हैं। परीक्षाफल आने के बाद उपजे असंतोष के कारण क्या होते हैं, इस पर कभी सार्थक चिंतन नहीं होता। कई वर्षों पहले विद्वान् शिक्षा-विशेषज्ञों के परामर्श से बात बन जाती थी, लेकिन अब सारे समीकरण राजनेताओं के परामर्श से बनते हैं। नब्बे प्रतिशत से ऊपर तक अंक पाने वाले बच्चों के अभिभावक भी आजकल की परीक्षा प्रणाली से खुश नहीं है, तो क्या यह चिन्ता का विषय नहीं?

जिस तरह आजकल पेपर लीक होने के समाचार आते हैं, उन्हें पढ़कर समझते हुए स्कूली बच्चे भी भविष्य की चिन्ता में खोये नजर आते हैं। सत्ता में बैठे हुए जिम्मेदार पल्ले झाड़ते हुए बयान देते हैं। पेपर लीक होना अब आम बात है। जो एजेंसियाँ हैं, उनमें कोई खौफ नहीं है। उनके लिये यह हर साल का काम है। शिक्षा का जब पूरी बाजारीकरण कर दिया गया है, तब किसी भी तरह की परीक्षा को भी बाजार से मुक्त कैसे रखा जा सकता है? कितने होनहार युवा उत्पीड़न के शिकार हुए, यह जानने और समझने जितनी संवेदना अब किसके पास बची है? यदि ऐसा ही चलता रहा, तो बच्चे भविष्य के सपने देखना ही छोड़ देंगे। इस राष्ट्रीय दुर्भाग्य के आगाज से बचने के लिये हम अब भी नहीं जागे, तो मुश्किलें बहुत बढ़ जायेंगी।

एक समय तक शिक्षकों को बाल-मनोविज्ञान में खास तौर पर प्रशिक्षित किया जाता था। ऐसा समझा जाता था कि जो शिक्षक बच्चों के मनोविज्ञान से वाकिफ नहीं, वह शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आ सकता। इन दिनों साठ-साठ बच्चों की पाँच-पाँच कक्षाओं में पढ़ाने वाले, और काम के बोझ से लदे हुए शिक्षकों के पास एक-एक बच्चे का मनोविज्ञान समझने का वक्त ही कहाँ होता है? इतने सारे बच्चों को वह व्यक्तिगत रूप से पहचान भी नहीं पाता। शिक्षक को इतना समय तो मिले, कि वह बच्चों के साथ काउंसिलिंग कर सके। बच्चों की पारिवारिक पृष्ठभूमि जानना शिक्षक के कितना जरूरी है, यह स्कूल प्रबंधन समिति कभी नहीं जान सकती। उसे केवल फीस से मतलब रहता है। बच्चे यदि स्कूल टीचर से नहीं खुल पायें, तो वे जीवन भर के लिये बंद रह जाते हैं।

छोटे और बड़े शहरों में, कस्बों में असंख्य स्कूल खुल गये हैं। इन स्कूलों में ए.सी. रूम्स हैं, सब तरह की सुविधाएँ हैं। बस वही नहीं है, जो बच्चों के मन को सहला सके। वही नहीं है, जो उनका रक्षा-कवच बन सके। ऊपर से नीचे तक शिक्षा व्यवस्था को इस तरह बना दिया गया है कि वह अभिभावकों की सालाना आमदनी का दोहन कर सके। वह व्यवस्था इस तरह आकर्षक मुद्रा में सामने जा खड़ी होती है, कि अभिभावक खिंचे चले आते हैं। अब तो यह भी मान लिया गया है कि जितना महंगा स्कूल, उतनी बेहतरीन शिक्षा। बदलाव कहाँ से आये? और कैसे आये? संस्कार न घर-परिवार दे पा रहे हैं, न हमारे स्कूल। अब भी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे।

मेलोनी, मोदी और 'मेलोडी' के बहाने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की नई भाषा

डॉ. सुदीप शुक्ल
(लेखक स्वतंत्र पत्रकार एवं विदेश मामलों के अध्येता हैं)

आधुनिक विश्व में अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का स्वरूप और शैलियां तेजी से बदली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की यात्रा में यह तथ्य एक बार फिर उभरकर सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की द्विपक्षीय भेंटवार्ता ने दुनिया का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। उनकी मुलाकात के फोटो और वीडियो मिनटों में ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड कर रहे थे। भारत में तो इस दौरे की सबसे अधिक चर्चा रही। वास्तव में अब अंतरराष्ट्रीय कूटनीति केवल बैठकों, समझौतों, संयुक्त बयानों और सामरिक साझेदारी तक ही सीमित नहीं रह गई है। संवाद, संचार माध्यमों, तकनीक, सोशल मीडिया से समृद्ध 21वीं सदी ने कूटनीतिक शिष्टाचार की नई भाषा गढ़ दी है।

यूरोप के छह दविसीय दौरे के अंतिम चरण में 19 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने रोम में प्रधानमंत्री मेलोनी से मुलाकात की। दोनों प्रधानमंत्री एक ही कार में भ्रमण पर गए और दो हजार वर्ष प्राचीन कोलोजियम में सेल्फी भी ली। मुलाकात के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रधानमंत्री मेलोनी को भारतीय चॉकलेट 'मेलोडी' भेंट करना सबसे अधिक चर्चा में रहा। कूटनीतिक शिष्टाचार की दृष्टि से यह एक साधारण सांस्कृतिक संकेत भर नहीं था बल्कि प्रतीकात्मक राजनीति, डिजिटल युग की ब्रांडिंग और सॉफ्ट पावर के संगम का बड़ा उदाहरण बन गया। सोशल मीडिया पर पहले से लोकप्रिय मोदी और मेलोनी के नामों के मिश्रण से बना हैशटैग 'मेलोडी' अचानक वैश्विक विमर्श का केंद्र बन गया।

मेलोनी और मोदी की भेंट, कॉलेजयिम में साथ में सेल्फी लेना, कार में सफर और मेलोडी चॉकलेट के उपहार को लेकर सोशल मीडिया पर जिस प्रकार के मीम्स की बाढ़ आई और हास्य उत्पन्न किया गया उससे उठे कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजना आवश्यक है। यदि प्रधानमंत्री मेलोनी स्त्री न होतीं तब भी क्या मेलोडी प्रसंग इतना अधिक चर्चित होता क्या इसी वर्ष राष्ट्रपति पुतिन के साथ कार में प्रधानमंत्री मोदी के भ्रमण को भी इसी नजरिए से देखा गया था बीते कुछ समय से उद्यान में घूमते, बातें करते, प्राचीन इमारतों को निहारते कई राष्ट्राध्यक्षों के दृश्य सामने आते रहे हैं लेकिन वे इस प्रकार के विमर्श के केंद्र में क्यों नहीं आ सके वास्तव में अंतरराष्ट्रीय कूटनीति सोशल मीडिया मनोरंजन से बहुत अलग होती है। वैश्विक राजनीति में 'व्यक्तिगत केमिस्ट्री' अब केवल निजी संबंध नहीं रह गई है बल्कि वह रणनीतिक पूंजी में बदल चुकी है।

मेलोडी प्रसंग के शोर में कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा दबकर रह गई। इस दौरे में दोनों देश भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) पर सहमत हुए हैं। यह परियोजना भारत को मध्य पूर्व और यूरोप के देशों से रेलवे, बंदरगाह और शिपिंग नेटवर्क के माध्यम से जोड़ेगी। इस परियोजना के पूरा होने पर भारत से यूरोप तक आयात-निर्यात में समय और लागत में 30 से 40 प्रतिशत तक कमी आएगी।

दोनों देशों के बीच संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना 2025-2029 पर रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर भी सहमति बनी है। दोनों देश आर्थिक सहयोग, निवेश, कनेक्टविटी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप, एआई के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। सुपरकंप्यूटिंग, रक्षा, अंतरक्षि, संस्कृति-शैक्षिक आदान-प्रदान, भारत-यूरोपीय संघ संबंध सहित बहुपक्षीय सहयोग पर भी सहमति बनी है। संयुक्त घोषणापत्र में पहलगांव हमले और आतंकवाद की निंदा भी की गई है।

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में राष्ट्राध्यक्षों और राजनयिकों की मुलाकात के दौरान शारीरिक भाषा भी गहरे राजनीतिक अर्थ देती है। मुस्कुराहट का एक-एक मिलीमीटर कम-ज्यादा होना, आंखों की स्थिरता, हाथ मिलाने का समय और अभिवादन का तरीका इन सबसे संबंधों की आत्मीयता, गर्मजोशी या ठंडेपन का अनुभव हो जाता है। कई बार तो दौरों से पहले इस कूटनीतिक शिष्टाचार को लेकर विशेष रणनीति भी तैयार की जाती है। डेलीगेट्स का व्यवहार अभिवादन की पहल किसने की जैसे कई संकेत संबंधों की कसौटी पर कसे जाते हैं।

भारतीय विदेश नीति सदैव से बेहद संतुलित और सतर्क किन्तु उदार रही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहराव के समय भारतीय कूटनीति ने थोड़ी अलग शैली में काम करना शुरू किया लेकिन तब भी विपक्ष के एक नेता अपने भाषण में इस बात का उल्लेख करते थे कि हमारे प्रधानमंत्री यदि विदेश जाते हैं तो वहां के अखबारों में एक कॉलम की छोटी सी खबर छपती है। आज परस्थितियां बदल चुकी हैं। भारत की दमदार छवि दुनिया के सामने है। ऐसे में कूटनीतिक शिष्टाचार और शैलियां भी बदलना स्वाभाविक ही है। इसी दौरे के प्रारंभ में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचने पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने स्वयं एयरपोर्ट पहुंचकर मोदी की अगवानी की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के वायुयान को यूएई वायुसेना के एफ-16 विमानों ने सम्मानपूर्वक एस्कार्ट किया था। इसके पूर्व इसी साल जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर राष्ट्रपति शेख जायद की अगवानी की थी। यह कूटनीतिक शिष्टाचार अपनत्व और भरोसे को भी दर्शाता है।

मोदी और मेलोनी के संबंधों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति पहली बार 2023 के जी-20 और कॉप-28 सम्मेलनों में चर्चा में आई थी जब मेलोनी ने स्वयं सोशल मीडिया पर हैशटैग 'मेलोडी' का प्रयोग किया था। असल में 'सॉफ्ट डिप्लोमेसी' अब केवल फिल्मों, योग, खान-पान या सांस्कृतिक आयोजनों तक सीमित नहीं है। डिजिटल युग में एक मुस्कान, एक सेल्फी, एक प्रतीकात्मक उपहार या एक वायरल वीडियो भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दिशा तय करने में भूमिका निभा सकता है। रोम में 'मेलोडी' टॉफी का आदान-प्रदान भले ही हल्का फुल्का दृश्य प्रतीत हो किन्तु उसके पीछे भारत और इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी का व्यापक परिप्रेक्ष्य मौजूद था।

हालांकि इस प्रकार की 'इवेंट आधारित डिप्लोमेसी' की आलोचना भी होती है। विपक्षी नेताओं और सोशल मीडिया के एक वर्ग ने इसकी आलोचना की हैं। इसके बावजूद यह भी उतना ही सत्य है कि आधुनिक राजनीति में प्रतीक और मनोविज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुके हैं। जनता अब केवल नीति पत्र नहीं पढ़ती बल्कि वह दृश्य और भावनात्मक संकेतों से भी राजनीतिक धारणा बनाती है।

असल प्रश्न यह नहीं है कि 'मेलोडी' टॉफी क्यों दी गई, बल्कि यह है कि एक साधारण भारतीय उत्पाद वैश्विक मंच पर सांस्कृतिक पहचान का माध्यम कैसे बन गया। यही सॉफ्ट पावर की सफलता है। कभी जापान ने एनीमे और टेक्नोलॉजी से, अमेरिका ने हॉलीवुड से, दक्षिण कोरिया ने के-पॉप से और चीन ने पांडा डिप्लोमेसी से अपनी पहचान बनाई। आज भारत भी अपनी सांस्कृतिक सहजता और डिजिटल संवाद शैली के माध्यम से एक नया कूटनीतिक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। भारत ने पिछले एक दशक में योग, जी20, डिजिटल इंडिया, वैक्सीन मैत्री और प्रवासी भारतीय कूटनीति के माध्यम से कूटनीति की नई शैली विकसित करने का प्रयास किया है।

मोदी और मेलोनी का यह प्रसंग यह भी बताता है कि भविष्य की डिप्लोमेसी केवल बंद कमरों में नहीं चलेगी। वह सोशल मीडिया की टाइमलाइन, वायरल वीडियो और जनमानस की स्मृति में भी निर्मित होगी। अंतरराष्टीय संबंधों का यह नया युग है जिसमें नेता केवल राष्ट्राध्यक्ष नहीं बल्कि वैश्विक पहचान भी बन चुके हैं। जनभावनाओं और डिजिटल इमेज आधारित कूटनीति अब नया आकार और प्रभाव ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी के बीच हाल ही में चर्चा में आया 'मेलोडी डिप्लोमेसी' का प्रसंग इसी बदलती वैश्विक राजनीति का प्रतीक है। वास्तव में यह बदलते कूटनीतिक शिष्टाचार की नई भाषा है जिसे शिष्टाचार के साथ पढ़ा जाना जरूरी है।

शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के खातों को किया जा रहा अपडेशन

जिले के 1718 विद्यार्थियों को मिलेगी लैपटॉप हेतु 25-25 हजार की राशि

एस द्विवेदी, बैतूल। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 12वीं में 75 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंकों के साथ उत्तीर्ण होने वाले छात्र-छात्राओं को लैपटॉप देने की योजना वर्ष 2013-14 से शुरू की गई थी। जिसके बाद हर साल शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों के नियमित छात्र-छात्राओं को सरकार द्वारा लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए की राशि दी जाती है। इस वर्ष लैपटॉप योजना के लिए जिले के 1,718 विद्यार्थी चयनित हुए हैं, इन विद्यार्थियों को शासन द्वारा लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपये की राशि जल्द ही मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से जिले के 75 फीसदी से ज्यादा अंक लाने वाले छात्र-छात्राओं की सूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बैतूल को भेजी गई है। जिसके अंतर्गत जिले के शासकीय एवं अशासकीय हायर सेकंडरी स्कूलों के 1,718 छात्र-छात्राओं को लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। यह राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में जाएगी। इस लिहाज से जिले में 1,718 छात्रों को करीब 4 करोड़ 29 लाख 50 हजार रुपए की राशि जल्द ही जारी होगी। इस वर्ष भी कक्षा 12वीं में 75 प्रतिशत अंक या उससे अधिक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप की राशि 25-25 हजार रुपए दी जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।

विद्यार्थियों के खातों का किया जा रहा अपडेशन- शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के खातों का अपडेशन किया जा रहा है। अब लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा मांगा गया ब्योरा अपडेट करने का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है। लैपटॉप योजना के तहत उन विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की परीक्षा, 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण की है। नियम यह है कि यह अंक विद्यार्थी के पहले ही प्रयास में आने चाहिए, अर्थात प्रथम बार में। श्रेणी सुधार वाले विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस साल भी मंडल ने कक्षा 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। इसके बाद लैपटॉप की राशि के लिए पात्र विद्यार्थियों का चयन भी कर लिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश ने हर जिलों के पात्र विद्यार्थियों की सूची, उन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भिजवा दी गई है।

अपडेट करना है यह जानकारियां- लैपटॉप राशि के लिए पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों की एंट्री पोर्टल पर करना है। इसके लिए जरूरी है कि उनका बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में हो, खातों का ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से हो और यह सुनिश्चित करना होगा कि उस बैंक खाते की लिमिट 25 हजार रुपये से कम न हो। अंसचालित और बंद खाते की एंट्री किसी भी हाल में न करने को कहा गया है। यह कार्य 15 दिनों के अंदर पूरा करना है। इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए जिले में 2 नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं। इनमें हाईस्कूल ताईखेड़ा के प्रभारी प्राचार्य अनिल कोकाटे और रायआमला हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य योगेश लाड़ शामिल हैं। इन्हें ऑपरेटर भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि बैंक खातों की समुचित जानकारी तेजी से अपडेट की जा सके। जानकारी लेकर स्कूलों के प्राचार्यों को ही बुलाया जा रहा है और उनकी मौजूदगी में ही जानकारी अपडेट कराई जा रही है।

पिछले सत्र से इस वर्ष बढ़ी विद्यार्थियों की संख्या- इस वर्ष बैतूल जिले में 1,718 विद्यार्थियों का चयन लैपटॉप योजना के लिए हुआ है। जबकि विगत वर्ष लैपटॉप योजना में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या जिले में कम थी। जिला शिक्षा अधिकारी बैतूल भूपेंद्र वरकड़े ने बताया कि विगत वर्ष 2025 में जिले के कुल 1027 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 25-25 हजार रुपए की राशि मिली थी। जबकि वर्ष 2024 में 1192 छात्र-छात्राएं इसके लिए पात्र थे। इस साल विगत वर्ष की तुलना में 691 विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। इस बार जिले में पिछले वर्ष की तुलना में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 1,718 हो गई है और परीक्षा परिणाम भी पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहा है।

जैव विविधता संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर काम जरूरी : डॉ. हर्षवर्धन यादव

पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बैतूल में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर हुई कार्यशाला

बैतूल। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जयवंती हक्सर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बैतूल में इको क्लब के तत्वावधान में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ मीनाक्षी चौबे के मार्गदर्शन में किया गया। इको क्लब प्रभारी प्रोफेसर अर्चना सोनारे ने वनस्पति विभाग में वृक्षारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य वक्ता डॉ हर्षवर्धन यादव, विधि महाविद्यालय बैतूल ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न कानूनों की जानकारी देते हुए कहा कि पंचायत स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक सामूहिक प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण संभव है। प्रोफेसर अर्चना सोनारे ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर मौजूद पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण को प्रोत्साहित करना है।

भरत कुसुम मोदी अतिथि भवन के नवनिर्माण हेतु भुमि पूजन हुआ

धार। दिगंबर जैन समाज धार की रघुनाथपुरा स्थित पुरानी धर्मशाला के स्थान पर भव्य भरत कुसुम मोदी अतिथि भवन का निर्माण किया जाएगा। नवीन अतिथि भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन करने का सौभाग्य नरेश कुमार श्रेणिक कुमार गंगवाल परिवार को प्राप्त हुआ। गुरुवार को प्रातः गुरु मां क्षुल्लिका 105 चंद्रमति माताजी के परम सानिध्य एवं विद्वान पंडित विमल जैन शास्त्री के मार्गदर्शन में भूमि पूजन कर कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। जानकारी देते हुवे समाज अध्यक्ष श्रेणिक गंगवाल, मीडिया प्रभारी संजय गंगवाल ने बताया कि यह अतिथि भवन तीन मंजिला बनेगा तथा आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न होगा। इस अवसर पर समाज के सभी सदस्यों की उपस्थिति रही।

कलेक्टर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, उपार्जन केंद्र, कृषि सहकारी समिति का किया निरीक्षण

हाई रिस्क और एनीमिक महिलाएं समय पर अपनी आवश्यक खुराक लें, इसकी नियमित मॉनिटरिंग हो : कलेक्टर डॉ. सोनवणे

बैतूल। घोड़ाडोंगरी जनपद के विभिन्न ग्रामों के भ्रमण के दौरान शुक्रवार को कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने रानीपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, उपार्जन केंद्र, कृषि सहकारी समिति का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी, आईपीडी एवं विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी डॉक्टरों से ली। उन्होंने निर्देश दिए कि रोस्टर के अनुसार डॉक्टरों की नियमित ड्यूटी लगाकर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएं। साथ ही बारिश से पूर्व स्वास्थ्य केंद्र भवन की आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने बीएमओ से पीएम संबंधी शिकायतों की जानकारी लेकर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य प्रबंधन, प्रथम त्रैमासिक एएनसी पंजीयन तथा हाई रिस्क एवं एनीमिक महिलाओं को दिए जा रहे उपचार की जानकारी ली। इस दौरान बीएमओ ने हाई रिस्क और एनीमिक महिलाओं को दिए जा रहे उपचार की जानकारी दी, जिस पर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि हाई रिस्क और एनीमिक महिलाएं समय पर अपनी आवश्यक खुराक ले, इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। इसके अलावा उन्होंने आयरन सुक्रोज सहित अन्य आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश भी दिए। बीएमओ ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ाडोंगरी में सोनोग्राफी सेवाएं भी पूरी तरह क्रियाशील हैं। इस दौरान कलेक्टर ने घोड़ाडोंगरी को एक बेहतर स्वास्थ्य मॉडल के रूप में विकसित करने तथा क्षेत्र में मातृ एवं शिशु मृत्यु शून्य रखने के लिए प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए।

आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचकर बच्चों से किया आत्मीय संवाद, भोजन की गुणवत्ता परखी- कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने रानीपुर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने बच्चों से आत्मीय संवाद कर उन्हें बिस्किट एवं चॉकलेट वितरित किए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों की दर्ज संख्या, नाश्ता एवं भोजन व्यवस्था की जानकारी ली तथा भोजन चखकर गुणवत्ता भी परखी। भोजन हल्का तीखा पाए जाने पर उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से जानकारी ली। कार्यकर्ता ने बताया कि बच्चे सहज रूप से तीखा भोजन ग्रहण कर लेते हैं। कलेक्टर ने आंगनवाड़ी में उपलब्ध फर्स्ट एड किट का निरीक्षण कर बीएमओ को आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

कलयुग का अंत निकट है, सतयुग का आगमन होगा : श्री मिश्र

- हीरालाल गोलानी

भोपाल। श्रीमद्भागवत कथा के उपरांत शुक्रवार को जगन्नाथ संस्कृति के विशारद विद्वान डॉ काशीनाथ मिश्र उड़ीसा ने आयोजक पंकज खूबचदानी एवं नीरजा गोलानी खूबचदानी के इन्द्र विहार कालोनी पंचवटी परिसर भोपाल में इस प्रतिनिधि से अपना मत व्यक्त करते बताया कि अभी चार किस्म की वायु संसार में विद्यमान है ।एक ऐसा समय भी आएगा। संसार में 49 किस्म की चलने लगेगी पूरे संसार में त्राहि-त्राहि मच जाएगी। बिजली ठप्प हो जाएगी। खाने की चीजों का अभाव हो जाएगा। आएगा कल्कि अवतार ...कलयुग का अंत निकट है। मुरादाबाद संभल उत्तरप्रदेश में कल्कि अवतार हो चुका है। जगन्नाथ संस्कृति के विशारद विद्वान पंडित डॉ काशीनाथ मिश्र उड़ीसा ने कहा कि श्रीमद्भागवत महापुराण में उल्लेख है कि तीन राशि, रवि चंद्र बृहस्पति देव कर्क पुष्य नक्षत्र में सन् 2032 में सतयुग का आगमन हो इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं उड़िया भाषा में लिखित दुर्लभ ग्रंथ के आधार पर कह रहे हूं। मैंने 40 सालों से उक्त उड़िया लिखित भविष्य मालिका पुराण का अध्ययन किया है।लेकिन इसके पहले पूरे संसार विश्व में उथल-पुथल हो जाएगी। जो मानव धर्म पर आधारित नागरिक जीवित बच पाएंगे। आपने कहा कि जब तक सांस में सांस है तब तक जीवन उत्थान के पूरे विश्व में जनजागरण अभियान चलाकर नागरिकों को आगाह करता रहूंगा। आपने विश्व के मानव से त्रिकाल संध्या का जप अवश्य करें। इससे कोई बड़ा समय नहीं लगता। मै यह भी नहीं कहता कि जो आप पूजा कर रहे हैं करते रहे। लेकिन जीवन रक्षा के लिए त्रिकाल संध्या अवश्य करें। इसके साथ ही श्रीमद्भागवत कथा का एक अध्ययन प्रतिदिन पढ़ें। इससे आपकी सुरक्षा के साथ उम्र में भी बढ़ोतरी होगी। सतयुग धारा में जाने लायक बनेंगे। श्रीमद्भागवत पुराण समुद्र के समान है। जैसे नदियां समुद्र में विलीन हो जाती है। वैसे ही श्रीमद्भागवत महापुराण सबसे महत्वपूर्ण है । आपने दावा किया कि सतयुग के सन् 2032 में सतयुग के आगमन के उपरांत गो, वानर पशु, आदि भी बात करेंगे।

होगा तृतीय विश्व युद्ध- जगन्नाथ संस्कृति के श्री मिश्र ने आगे बताया कि भविष्य मालिका पुराण के आधार पर कहा कि 2027 में भारत पर पाकिस्तान हमला करेगा, लड़ाई थोपेगा। चीन भी न,ना करके पाकिस्तान का साथ देगा। चीन उत्तरांचल से हमला करेगा। इस भीषण युद्ध में 57 मुस्लिम देश पाकिस्तान का साथ देंगे। नेपाल, लंका के अलावा अमेरिका, नाटों देश भी इस युद्ध में कूद पड़ेंगे। जापान, जर्मन फ्रांस मददगार साबित होंगे।

इस भीषण युद्ध में परमाणु हथियार का उपयोग होगा। लेकिन कल्कि अवतार के कारण इसका असर नाम मात्र ही रहेगा। जगन्नाथ से वर प्राप्त रूस भारत की सहायता करेगा। सारे संसार में खलबली मच जाएगी कि भारत पर परमाणु हथियार के हमले का असर क्यों नहीं हुआ? सारे विश्व चर्चा होगी कि परमाणु हथियार ने कार्य क्यों नहीं किया। सभी भारत से डरेंगे अमेरिका, नाटों देश खंड खंड हो जाएंगे कल्कि अवतार से आग्रह करेंगे रक्षा करो रक्षा करो। मैंने उड़िया भाषा में लिखित दुर्लभ ग्रंथ का अध्ययन लगातार 40 साल किया है। इसी आधार पर मैं पूरे विश्व में जनजागरण अभियान चलाकर कथा करता हूं। आपने अलग-अलग प्रांतों में होने वाली कथाओं के स्थानों का उल्लेख करते कहा कि मैं एक दिन भी विश्राम नहीं करता हूं। मानव रक्षार्थ। आपने अंत इस प्रतिनिधि से कहा कि मैं पूरे भारत सहित विदेश में आयोजित होने वालीकथा का पैसा नहीं लेता हूं। मानव जाति का कल्याण हो यही मेरा संकल्प है। आप अपना भविष्य एवं अपना जीवन बचाने के लिए त्रिकाल संध्या, श्रीमद्भागवत पुराण, भविष्य मालिका पुराण का अध्ययन करें । इसके साथ ही माधव, माधव भजे, मानव सभ्यता का कल्याण होगा।

किया श्री विष्णु हवन- आज शुक्रवार को श्रीमद्भागवत कथा एवं भविष्य मालिका पुराण कथा आयोजक पंकज खूबचदानी एवं नीरजा गोलानी खूबचदानी के निवास पर जगन्नाथ संस्कृति के विशारद विद्वान पंडित डॉ काशीनाथ मिश्र उड़ीसा ने श्री विष्णु हवन का मंत्रोच्चारण के साथ हवन कराया ।इस हवन आयोजक के अलावा पत्रकार हीरालाल गोलानी सोहागपुर, दिनेश मुल्तानी जबलपुर, विशाल गोलानी सोहागपुर सहित महाकालेश्वर भव धारा मंडल उज्जैन की मातृशक्ति एवं सदस्य उपस्थित थे।

आयुष विभाग के स्वर्ण प्राशन अभियान में 470 बच्चों ने लिया लाभ

पुष्य नक्षत्र पर आयोजित स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न

बैतूल। आयुष विभाग द्वारा 21 मई को जिले में स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 470 बच्चों ने लाभ प्राप्त किया। जिला आयुष अधिकारी एवं बाल्य रोग विशेषज्ञ डॉ. योगेश चौकीकर ने बताया कि प्रत्येक माह पुष्य नक्षत्र के अवसर पर स्वर्ण प्राशन कराया जाता है। इस माह भी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि स्वर्ण प्राशन औषधि में स्वर्ण भस्म के साथ शंखपुष्पी, ब्राम्ही, वचा तथा घृत और शहद का मिश्रण उपयोग किया जाता है। बदलते मौसम में यह बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और बीमारियों से लड़ने की शक्ति मजबूत करने में सहायक माना जाता है। आयुष विभाग के अनुसार स्वर्ण प्राशन बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए लाभकारी है। कार्यक्रम के तहत शासकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय टिकारी में 318 बच्चों, जिला आयुष विंग बैतूल में 46 बच्चों, शासकीय आयुर्वेद औषधालय गर्ग कॉलोनी में 81 बच्चों तथा शासकीय आयुर्वेद औषधालय भैंसदेही में 25 बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया। आयुष विभाग ने जिले के सभी अभिभावकों से 6 माह से 16 वर्ष तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराने के लिए आयुष केंद्रों पर लाने की अपील की है।

संक्षिप्त समाचार

ग्यारसपुर की ऐतिहासिक जिंद बाबा की बावड़ी में चलाया सफाई अभियान

विदिशा (निप्र)। प्रदेशव्यापी जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत ग्यारसपुर में जल संरक्षण और ऐतिहासिक धरोहरों के संवर्धन को लेकर मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में ग्यारसपुर की प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक जिंद बाबा की बावड़ी में व्यापक साफ-सफाई की गई। हाईवे किनारे स्थित इस प्राचीन बावड़ी की वर्षों से उपेक्षित पड़ी संरचना को स्वच्छ और संरक्षित करने के उद्देश्य से जनभागीदारी के साथ यह विशेष अभियान आयोजित किया गया। अभियान के दौरान बावड़ी परिसर में जमा गंदगी, झाड़ियां एवं कचरे को हटाकर साफ-सफाई की गई। उपस्थित जनसमुदाय ने जल स्त्रोतों के संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि प्राचीन बावड़ियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर होने के साथ-साथ जल संरक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम भी हैं। ऐसे ऐतिहासिक जल स्त्रोतों को बचाना आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की जिला समन्वयक पूजा श्रीवास्तव, ब्लॉक समन्वयक सुदेश आचार्य, नवांकुर संस्था युवा परिवर्तन सेवा समिति मणिपुर के शैलेंद्र रघुवंशी, मढी चौबीसा गुलाबगंज के गोलू दांगी, महेश बैरागी, परामर्शदाता राय बहादुर यादव, ओमप्रकाश यादव, मोहनपुर समिति के अध्यक्ष सीताराम कुशवाहा, भागवत लोधी सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता एवं ग्रामीणजन मौजूद रहे।

डिप्टी सीईओ ने किया ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण, स्ट्रांग रूम एवं सीसीटीवी व्यवस्था का लिया जायजा

नर्मदापुरम (निप्र)। कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी भोपाल के डिप्टी सीईओ संजय श्रीवास्तव द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री श्रीवास्तव ने वेयरहाउस परिसर में स्थित तीनों स्ट्रांग रूम का बाहरी निरीक्षण किया तथा सीसीटीवी कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था एवं ईवीएम के रखरखाव संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि वेयरहाउस स्थित स्ट्रांग रूम में कुल 1937 बैलेट यूनिट, 1756 कंट्रोल यूनिट एवं 1784 वीवीपैट सुरक्षित रखी गई हैं। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इन मशीनों का मासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तथा त्रैमासिक निरीक्षण मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराया जाता है। निरीक्षण के दौरान निर्वाचन सुपरवाइजर कैलाश दुबे, मास्टर ट्रेनर पंकज दुबे सहित निर्वाचन कार्यालय के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

वॉल्वमेन एवं पंप ऑपरेटरों को दिया गया पानी की टंकियों की सफाई का प्रशिक्षण

सीहोर (निप्र)। जल गंगा अभियान के अंतर्गत शासकीय शालाओं में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीहोर जनपद पंचायत एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वॉल्वमेन एवं पंप ऑपरेटरों को एसबीएम (स्वच्छ भारत मिशन) के तहत 'वॉश ऑन व्हील' के माध्यम से पानी की टंकियों की वैज्ञानिक एवं सुरक्षित तरीके से सफाई करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सीहोर जनपद पंचायत कार्यालय में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा टंकियों की नियमित सफाई, पानी की गुणवत्ता बनाए रखने, क्लोरीनेशन प्रक्रिया तथा स्वच्छता संबंधी आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए समय-समय पर पानी की टंकियों की सफाई सुनिश्चित करना जरूरी है। कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि जल गंगा अभियान का उद्देश्य जल स्त्रोतों एवं पेयजल व्यवस्थाओं को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखना है। 'वॉश ऑन व्हील' तकनीक के माध्यम से कम समय में प्रभावी ढंग से टंकियों की सफाई की जा सकती है, जिससे विद्यार्थियों को स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम में वॉल्वमेन, पंप ऑपरेटर एवं संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।

आदतन अपराधी 06 माह के लिए जिलाबदर

रायसेन (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में आरोपी राहुल बेदी पिता रतन सिंह बेदी निवासी ग्राम पठारी थाना कोतवाली रायसेन को 06 माह के लिए रायसेन जिला तथा रायसेन जिले के सीमावर्ती जिलों की राजस्व की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आरोपी वर्ष 2017 से लगातार आपराधिक कृत्य में लिप्त है। आरोपी के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में 09 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी राहुल बेदी को जिलाबदर करने संबंधी पारित आदेश के अनुसार जिला रायसेन एवं जिला रायसेन के सीमावर्ती जिला भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर, नर्मदापुरम् एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं से 06 माह के लिए निष्कासित किया गया है।

वीसी के माध्यम से की राजस्व प्रकरणों तथा सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा

राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण कराएं- कलेक्टर श्री विश्वकर्मा

रायसेन (निप्र)। जिले में राजस्व प्रकरणों तथा सीएम हेल्पलाईन शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा प्रतिदिन वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से कार्य प्रगति की समीक्षा की जा रही है। प्रतिदिन की जा रही समीक्षा के सकारात्मक परिणाम भी परिलक्षित हो रहे हैं। राजस्व प्रकरणों एवं सीएम हेल्पलाईन शिकायतों के निराकरण में उल्लेखनीय गति आई है तथा लंबित मामलों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। अधिकारियों द्वारा मैदानी स्तर पर सक्रियता बढ़ाते हुए शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है।

कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा द्वारा गुरूवार को भी प्रातः कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अनुभाग और तहसीलवार राजस्व प्रकरणों तथा सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी एसडीएम तथा तहसीलदारों से गत दिवस निराकृत किए गए राजस्व प्रकरणों, निराकरण हेतु शेष प्रकरणों तथा आज निराकृत किए जाने वाले प्रकरणों की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में गति लाएं तथा सभी एसडीएम इसकी प्रगति की नियमित समीक्षा करें। इसी प्रकार खाद वितरण हेतु शुरू की गई ई-विकास टोकन प्रणाली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, किसानों तक विभिन्न माध्यमों से इसकी जानकारी पहुंचाई जाएं तथा उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु मैदानी अमले को निर्देशित करें। उन्होंने 50 दिवस से अधिक समयावधि वाली शिकायतों का गंभीरता से परीक्षण कर निराकरण कराने के निर्देश भी दिए। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने सभी एसडीएम तथा अन्य अधिकारियों से कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का गंभीरतापूर्वक निराकरण कराएं और निराकरण की कार्यवाही से आवेदक को अवगत कराएं। साथ ही प्रतिवेदन जिला स्तर भी भेजें। उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से निराकृत किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने मानूसन के दृष्टिगत सभी आवश्यक तैयारियां किए जाने के संबंध में भी दिशा-निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। विकासखण्डों से सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा अन्य अधिकारी वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे।

धरती आबा एवं पीएमजनमन अभियान के अंतर्गत ग्रामों में शिविर आयोजित

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने और शासकीय योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिलाने के लिए धरती आबा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत जिले में 18 मई से 25 मई तक जनजातीय समुदाय के लिये लाभार्थी संतृप्ति शिविर, जन भागीदारी सबसे दूर, सबसे पहले का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत 21 मई को जिले के ग्राम सालीखेड़ा, भीलखेड़ा खुर्द और आंवलीखेड़ा सहित चिन्हित ग्रामों में शिविर लगाए गए और पात्र हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। अभियान के अंतर्गत जिले के चयनित 80 ग्रामों में शिविर आयोजित कर जनजातीय क्षेत्रों के पात्र हितग्राहियों को शिविरों में विभिन्न विभागों के समन्वय से आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जनधन खाता, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान, पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस प्रोग्राम, सिकल सेल मिशन, क्षय रोग उन्मूलन जाँच, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, राशन कार्ड, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा, सुकन्या समृद्धि योजना और वन अधिकार पट्टा सहित अनेक योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

कलेक्टर के निर्देश पर सिवनी मालवा में प्रशासन एवं आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार सिवनी मालवा तहसील क्षेत्र में मदिरा दुकानों के आसपास संचालित अवैध गतिविधियों एवं अव्यवस्था फैलाने वालों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) सिवनी मालवा श्री विजय राय के नेतृत्व में प्रशासन एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा क्षेत्र में सघन निरीक्षण एवं कार्रवाई अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान मदिरा दुकानों के आसपास अवैध रूप से संचालित गुमटियों, ढाबों एवं लोगों को बैठाने की व्यवस्था का जायजा लिया गया। जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। एसडीएम श्री विजय राय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मदिरा दुकानों के आसपास किसी भी प्रकार के अवैध अहाते संचालित नहीं होने दिए जाएंगे। कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग सिवनी मालवा की टीम द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 36 (अ) के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध 02 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए। वहीं निरीक्षण के दौरान बनापुरा स्थित मदिरा दुकान के समीप एक बंद पड़ी अवैध गुमटी पाई गई, जिसे सुरक्षात्मक दृष्टि से तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए। मौके पर उपस्थित मुख्य नगरपालिका अधिकारी सिवनी मालवा को उक्त अवैध गुमटी को तत्काल प्रभाव से हटाने हेतु निर्देशित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी श्री विजय राय ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

गेहूँ उपार्जन केन्द्र हाजीपुर पहुँचे राज्य सहकारी बैंक के प्रशासक

ऊर्जा संरक्षण, हरित सहकार अभियान एवं सदस्यता महाअभियान की प्रगति की समीक्षा

विदिशा (निप्र)। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित विदिशा की शाखा सिरोंज अंतर्गत समिति हाजीपुर के गेहूँ उपार्जन केन्द्र का निरीक्षण म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के प्रशासक महेन्द्र सिंह यादव द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपार्जन केन्द्र पर पहुँचकर किसानों से सीधे संवाद किया तथा गेहूँ उपार्जन व्यवस्था, तौल एवं भुगतान संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। प्रशासक श्री यादव ने सहकारिता गतिविधियों, ऊर्जा संरक्षण, सदस्यता महाअभियान तथा हरित सहकार अभियान की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए किसानों, बैंक अधिकारियों एवं समिति कर्मचारियों से चर्चा की। उन्होंने वर्तमान वैश्विक ऊर्जा संकट का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 'ईंधन बचाओ-ऊर्जा बचाओ' संदेश को अपनाने की अपील की।

उन्होंने सहकारिता एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों से ऊर्जा संरक्षण के प्रति सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को बढ़ावा देने एवं स्थानीय उत्पादों के अधिकाधिक उपयोग का संदेश भी दिया गया। साथ ही 'एक पेड़ माँ के नाम' वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत बैंक मुख्यालय एवं पैक्स स्तर पर पौधरोपण के निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। प्रशासक महोदय ने 'हरित सहकार अभियान' के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री 1 द्वारा घोषित 'कृषक कल्याण वर्ष-2026' के अंतर्गत 14 अप्रैल से 30 जून 2026 तक संचालित सदस्यता महाअभियान की भी समीक्षा की गई। श्री यादव ने अधिक से अधिक किसानों को सहकारी समितियों से जोड़ने एवं निर्धारित समय-सीमा में सदस्यता कार्य पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। प्रशासक श्री यादव ने किसानों से ई-विकास प्रणाली के अंतर्गत ई-टोकन के माध्यम से खाद वितरण व्यवस्था सहित अन्य विषयों पर भी संवाद किया। उन्होंने सुझाव दिया कि बी-पैक्स संस्थाओं की वार्षिक आमसभा में चयनित सदस्य किसानों को सम्मानित किया जाए, जिससे किसानों का उत्साहवर्धन हो सके। भेंट के दौरान विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री अभय प्रधान, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनय प्रकाश सिंह, प्रबंधक योजना एवं विकास श्री सत्य प्रकाश आर्य, विपणन अधिकारी श्री विजय कुमार साहू तथा शाखा सिरोंज के शाखा प्रबंधक श्री प्रकाश बाबू शर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

अनुशंसा से अधिक उर्वरक उठाव करने वाले कृषकों से कृषि विभाग ने किया संपर्क

संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा परीक्षण एवं प्राकृतिक खेती अपनाने की दी सलाह

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा से प्राप्त निर्देशों के पालन में कृषि विभाग द्वारा उर्वरक उपयोग की निगरानी एवं कृषकों को जागरूक करने हेतु विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में 15 मई से अब तक अनुशंसा अनुसार उर्वरक उठाव करने के पश्चात पुनः अतिरिक्त उर्वरक लेने वाले 13 कृषकों से एटीएम एवं बीटीएम अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर संपर्क किया गया। अधिकारियों द्वारा कृषकों से अनुशंसा से अधिक मात्रा में उर्वरक उठाव के कारणों की जानकारी ली गई। कृषकों ने बताया कि धान फसल हेतु अग्रिम उर्वरक संग्रहण, मूंग की फसल कमजोर होने पर अतिरिक्त खाद का उपयोग, अन्य कृषकों को खाद देने, अन्य फसलों में उपयोग तथा सिकमी भूमि में प्रयोग के कारण पुनः उर्वरक उठाव किया गया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने कृषकों को मृदा परीक्षण के आधार पर प्राप्त मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अनुशंसा अनुसार ही उर्वरकों का उपयोग करने की सलाह दी। साथ ही फसल विविधीकरण, जैविक एवं प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कृषकों को समझाइश दी गई कि अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादन लागत बढ़ती है तथा मृदा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अधिकारियों ने कृषकों से जैविक खाद के उपयोग, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई एवं कम लागत वाली प्राकृतिक खेती पद्धतियों को अपनाने की अपील की। साथ ही भविष्य में संतुलित एवं आवश्यकतानुसार उर्वरक उपयोग करने संबंधी सलाह भी दी गई।

कृषि रथ ने साकादेही, कल्याणपुर और उड़दन के किसानों को उन्नत कृषि तकनीक की दी जानकारी

बैतूल (निप्र)। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के उपलक्ष्य में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा गुरुवार को बैतूल विकासखंड की ग्राम पंचायत साकादेही, कल्याणपुर एवं उडदन में 'कृषि रथ कार्यक्रम' का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों एवं शासन की विभिन्न कृषक हितैषी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना था। वरिष्ठ कृषि विस्वार विस्तार अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, खरीफ फसलों के बेहतर प्रबंधन, ई- टोकन प्रणाली, फार्मर आईडी, प्राकृतिक खेती तथा दलहन फसलों के महत्व के व पशुपालन, उघान विभाग के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही मिट्टी परीक्षण के लाभ एवं संतुलित उर्वरक उपयोग के विषय में किसानों को जागरूक किया गया। इस दौरान किसानों को नरवाई नहीं जलाने तथा फसल अवशेष प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे पर्यावरण संरक्षण एवं भूमि की उर्वराशक्ति बनाए रखी जा सके।

जल जीवन मिशन के तहत कलेक्टर श्री विश्वकर्मा की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक सम्पन्न

नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता

रायसेन (निप्र)। जल जीवन मिशन के तहत जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने संचालित और प्रगतिरत एकल नल जल योजनाओं तथा समूह नलजल योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा जल निगम के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने जिले में संचालित पेयजल योजनाओं की प्रगति, पाइपलाइन विस्तार, जल गुणवत्ता परीक्षण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने

प्रगतिरत नलजल योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि समयसीमा के भीतर नल-जल योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जाए। जिन निर्माण ठेकेदारों द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जा रही है या विलम्ब किया जा रहा है उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री गिरीश काम्बले ने बताया कि जिले में 755 ग्रामों में एकल नलजल योजना स्वीकृत हैं तथा इन ग्रामों में 136551 घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही प्रगतिरत नल जल योजनाओं का कार्य भी प्राथमिकता से पूर्ण कराया जा रहा है। इसी प्रकार जिले में संचालित और प्रगतिरत समूह नलजल योजनाओं की भी समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने कार्य में तेजी लाते हुए योजनाओं का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में जल निगम के अधिकारी द्वारा बताया गया कि उदयपुरा समूह जलप्रदाय योजना के माध्यम से 108 ग्रामों में 15383 घरेलू कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार बेगमगंज-गैरतगंज समूह जलप्रदाय योजना के माध्यम से 95 ग्रामों में 9941 घरेलू कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार जिले में प्रगतिरत समूह जलप्रदाय योजनाओं की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि हलाली समूह जलप्रदाय योजना का कार्य 85 प्रतिशत पूर्ण हो गया है। बेगमगंज एक्स 2 समूह जल प्रदाय योजना का कार्य 83 प्रतिशत, नर्मदा नदी समूह जल प्रदाय योजना का कार्य 65.88 प्रतिशत, गैरतगंज-सिलवानी समूह जल प्रदाय योजना का कार्य 43.49 प्रतिशत पूर्ण हो गया है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री कमल सोलंकी, डीएफओ श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय सहित पीएचई तथा जल निगम के जिला और विकासखण्डस्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

राइट क्लिक

क्या सर्वभक्षी कॉकरोच किसी बदलाव का प्रतीक हो सकता है?

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में प्राणियों और राजनीतिक दलों के प्रतीक चिन्हों में पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन मजाक में ही सही किसी राजनीतिक पार्टी का नाम किसी तुच्छ समझे जाने वाले जीव पर रखा जाए और सोशल मीडिया में उसके फॉलोअरों की बाढ़ आ जाए, ऐसा पहले शायद ही हुआ है। हैरानी की बात है कि एक मजबूत संगठन वाली सरकार भी 'कॉकरोच एप्रोच' से इतनी डर गई कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट बंद करा दिया। हालांकि इस कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के स्वघोषित जनक अभिजीत दिपके ने दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट चालू कर अपनी मुहिम चालू रखी। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आभासी जगत में नवोदित कॉकरोच जनता पार्टी समूचे सिस्टम में बदलाव की एक शुरूआती मगर अभिनव और गंभीर मुहिम है अथवा इसका अंजाम भी किसी तात्कालिक आंदोलन के नतीजे में धूमकेतु की माफिक उभरी और बाद में बोरिया बिस्तर समेटने वाली सियासी पार्टियों की तरह होगा?

वैसे भारत सहित कई देशों में राजनीतिक दल अपनी विचारधारा को प्रतीकात्मक स्वरूप देने के लिए कोई न कोई प्राणी चुनते रहे हैं। जैसे कि बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी है। पूर्वोत्तर की एक पार्टी एमजीपी का प्रतीक शेर है। लेकिन मानव समाज में सर्वाधिक मजाक का विषय और हेय दृष्टि देखा जाने वाला प्राणी गधा है, वह सियासी पार्टियों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। श्रीमती मेनका गांधी ने बहुत पहले लिखे एक लेख में बताया था कि दुनिया में 48 राजनीतिक दलों का प्रतीक चिन्ह गधा है, इनमें अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी भी शामिल है। गधे बेहद परिश्रमी होते हैं, लेकिन न तो बगावत करते हैं और न ही सवाल करते हैं। लेकिन सीजेपी ने तो कॉकरोच को अपना प्रतीक बनाया है। इसके पीछे तात्कालिक कारण भारत के प्रधान न्यायाधीश द्वारा एक सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी है, जिसमें उन्होंने तंज किया था कि देश में 'कॉकरोच' की तरह ऐसे युवा हैं, जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है। इनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया और कुछ आरटीआई और दूसरी तरह के एक्टिविस्ट बन रहे हैं। ये हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं।' व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों ने इसे अपने पर हमला माना। अमेरिका में पढ़ रहे अभिजीत दिपके को भी यह बात चुभी और उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल फेंका कि क्यों न सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं। इसे व्यापक समर्थन मिला। इसके बाद एक्स पर एक गूगल फॉर्म जारी हुआ। इसमें 'कॉकरोच जनता पार्टी' लिखी एक तस्वीर के साथ कैप्शन था- 'सभी कॉकरोचों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म। पार्टी जॉइन करने के लिए 4 जरूरी योग्यताएं बताई गईं- 'बेरोजगारी, आलसी, क्रॉनिकली ऑनलाइन, एबिलिटी टू रेंट प्रोफेशनली।'उसी दिन कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल X हैंडल- @CJP_2029, पार्टी की वेबसाइट cock-roachjantaparty.org और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया गया। इससे एक संदेश यह भी गया कि यह पहल कॉकरोच को समाज में मान्यता दिलाने और राजनीतिक दृष्टि से अन्य पार्टियों को चट कर जाने का भाव लिए हुए है। चूंकि आभासी दुनिया बिना हथियार के लड़ा जाने वाला महायुद्ध है, इसलिए स्थापना के महज पांच दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने डेढ़ करोड़ से ज्यादा फॉलोअर जुटा लिए। बताया जा रहा है कि इसमें हर घंटे 5 लाख फॉलोअर्स जुड़ रहे हैं। यह आंकड़ा बीजेपी और कांग्रेस के इंस्टाग्राम अकाउंट फालोअर्स से कहीं ज्यादा है। सीजेपी के हैंडल्स पर जो कंटेंट से बढ़ते यूथ कनेक्ट से इतना तो सिद्ध हुआ कि देश में बेरोजगार कितनी बड़ी संख्या में हैं।

सोशल मीडिया पर इस की राजनीतिक प्रतिक्रिया होनी ही थी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आज देश का युवा भयंकर गुस्से में है। उन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि वह युवाओं से सीधा संवाद करे।पूर्व क्रिकेटर और सांसद कीर्ति आज़ाद ने नई पार्टी में शामिल होने की इच्छा जताई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इसका समर्थन किया। राजनीतिक विश्लेषक योगेन्द्र यादव ने कहा कि यह देश के युवाओं में व्यवस्था को लेकर दबे असंतोष की सोशल मीडिया अभिव्यक्ति है, जो आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती है।

दूसरी तरफ नवजात सीजेपी पर अपना कानूनी मालिकाना हक जताने के लिए भी जंग शुरू हो गई है। मामला कॉकरोच जनता पार्टी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का है। इसके लिए दो लोगों ने आवेदन कर किए हैं। क्या इंटरनेट मीम और वायरल नामों पर भी मालिकाना हक तय किया जा सकता है? सोशल मीडिया यूजर्स इसे 'मीम ब्रांडिंग' और 'डिजिटल कब्जे' की नई लड़ाई बता रहे हैं। अगर किसी एक पक्ष को ट्रेडमार्क मिल जाता है, तो भविष्य में इस नाम के इस्तेमाल को लेकर कानूनी अधिकार भी तय हो सकते हैं।

सीजेपी औपचारिक रूप से चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड राजनीतिक दल नहीं है। इसकी वेबसाइट पर व्यंग्य में लिखा गया है कि ये 'कॉकरोचिस्तान के नो इलेक्शन कमीशन पर कॉकरोच एक्ट के तहत एक नॉन-रजिस्टर्ड पार्टी है।' तो क्या यह मुहिम सोशल मीडिया क्रांति के साथ ही खत्म हो जाएगी? इसके पीछे कारण यह है कि अभिजीत दिपके 2020 से 2022 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं। वो आप के लिए वायरल मीम बेस्ड ऑनलाइन प्रचार का मटेरियल बनाते थे। बाद में वो अमेरिका चले गए और वहां से भारत में राजनीतिक मुद्दों और मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी का कोई सीरियस घोषित एजेंडा नहीं है। लेकिन उसने अपने मैनिफेस्टो में 5 वादे किए हैं- अगर सीजेपी सरकार में आती है, तो किसी भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा जाने का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि किसी का वोटिंग राइट छीनना आतंकवाद से कम नहीं। महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण होगा, न कि 33%। इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी। कैबिनेट में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा। अंबानी और अडाणी के सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, ताकि वास्तव में स्वतंत्र मीडिया को जगह मिल सके। 'गोदी मीडिया' एंकरों के बैंक अकाउंट्स की जांच कराई जाएगी। अगर कोई विधायक या सांसद दलबदल कर दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाएगी। उसे अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस में पद नहीं दिया जाएगा। आदि।

कुछ लोग कॉकरोच को भारतीय राजनीति को मिला असामान्य प्रतीक मान रहे हैं। फिलहाल सीजेपी राजनीतिक व्यंग्य पर टिका ऑनलाइन आंदोलन है। हकीकत में सोशल मीडिया के ज्यादातर वीरों का असली दुनिया से वास्ता बहुत कम है। ये अपने में ही मगन और अपने तक सोचने वाली पीढ़ी ज्यादा है। स्पष्ट विचार, सोच, संगठन, प्रतिबद्धता और सक्षम नेतृत्व के बगैर कोई असंतोष बड़े और परिवर्तनकामी आंदोलन में नहीं बदल सकता। सोशल मीडिया के मौसमी उत्साह को अलग रखें तो सवाल यह है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य क्या है? क्या ये सिर्फ़ एक 'व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया अभियान' बनकर रह जाएगा या फिर सचमुच किसी देशव्यापी परिवर्तन का अग्रदूत बनेगा? इस बारे में सीजेपी के संस्थापक और आशावादी अभिजीत दिपके का मानना है कि ये सिर्फ़ शुरुआत है। अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि युवा इस राजनीतिक व्यवस्था को बदलना चाहता है। ऐसी व्यवस्था जहां हम तकनीकी रूप से एडवांस्ड हों जहां पर रोज़गार मिले। भारतीय जेन जी खुद के साथ कॉकरोच की तरह व्यवहार नहीं चाहता है। वह अपना पॉलिटिकल फ्रंट चाहता है। अभिजीत यह भी कहते हैं कि 'हम किसी भी पार्टी, खासतौर पर बीजेपी कस साथ अलायंस नहीं करेंगे। हम किसी मौजूदा पार्टी स्ट्रक्चर से जुड़ने में दिलचस्पी नहीं रखते। उनका यह भी कहना है कि 'नेपाल और बांग्लादेश के जेन-जी आंदोलनों से तुलना करके भारत के जेन-जी को कम न आंकें और न ही उनका अपमान करें। इस देश के युवा कहीं ज्यादा मैच्योर, जागरूक और राजनीतिक तौर पर सजग हैं।

एक बुनियादी प्रश्न यह भी है कि इस नई वर्चुअल पार्टी का नाम कॉकरोच पर ही क्यों? अगर कॉकरोच की नैसर्गिक गुणात्मकता पर जाएं तो वह एक अत्यधिक लचीला और परिस्थिति के अनुरूप खुद को अधिकतम ढाल कर जीवित रहने वाला प्राणी है। भले ही उसका रूप रंग घिन पैदा करने वाला हो। कॉकरोच का दुर्गुण यह है कि वह हर चीज को चट तो कर जाता है, लेकिन कोई नई चीज नहीं गढ़ता। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी का वैचारिक आधार क्या है? क्या इसका उद्देश्य केवल चालू व्यवस्था में सेंध लगाना है अथवा कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी देना है? वर्तमान सत्ता और व्यवस्था के प्रति आक्रोश भर जताना है या फिर देश को नई दिशा और विचार भी देना है? अगर इसमें सचमुच किसी बदलाव की आहट है तो उसका प्रतीक कॉकरोच कैसे हो सकता है?

गर्मी के बीच लंबा सिग्नल टाइम बना परेशानी

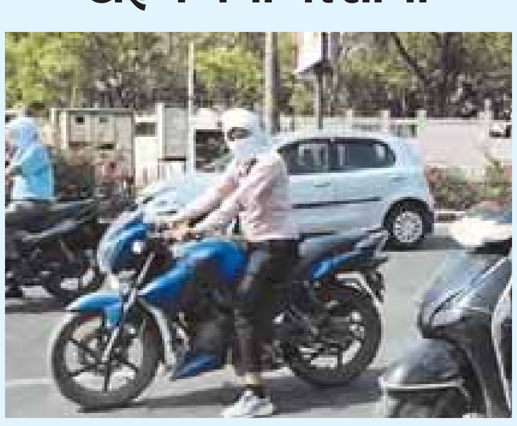

42 डिग्री तापमान में धूप में रुक रहे वाहन चालक, चौराहों पर ग्रीन नेट लगाने की मांग

भोपाल (नप्र)। भोपाल में भीषण गर्मी के बीच वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। शहर का तापमान 42 डिग्री पार पहुंच चुका है। इसके बावजूद चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल का समय एक मिनट या उससे ज्यादा है। लोगों को तेज धूप में लंबे समय तक सिग्नेल पर रुकना पड़ रहा है। गर्मी में सिग्नल पर खड़े रहने से दोपहिया वाहन चालक परेशान हैं। लोगों का कहना है कि लंबे सिग्नल टाइम की वजह से धूप और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों ने प्रशासन से मांग की है कि गर्मी को देखते हुए ट्रैफिक सिग्नलों की टाइमिंग कम की जाए। लोगों का यह भी कहना है कि दोपहर के समय कुछ प्रमुख चौराहों पर सिग्नल अस्थायी रूप से बंद किए जा सकते हैं। चौराहों पर टेंट या शेड लगाने की मांग भी उठ रही है, ताकि वाहन चालकों को तेज धूप से राहत मिल सके।

कॉकरोच पार्टी के जिक्र पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष खंडेलवाल का पलटवार

राहुल गांधी को दी मर्यादा में रहने की नसीहत

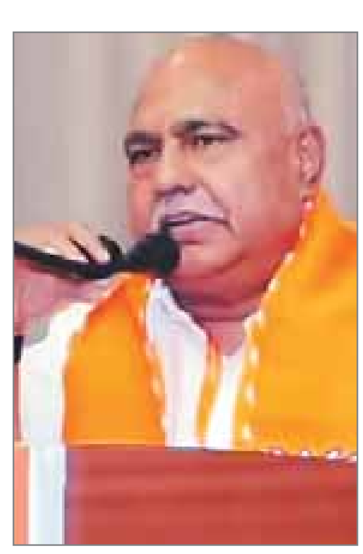

गुना (नप्र)। 'कॉकरोच जनता पार्टी' पर मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समय और परिस्थितियों के कारण ऐसी क्षणिक चीजों का उदय होता रहता है, लेकिन देश में स्थाई सिर्फ वही रहता है जहां लगातार काम होता है और जनता का विश्वास बना रहता है। देश में स्थाई सिर्फ भाजपा का काम है। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कॉकरोच पार्टी को लेकर देशभर में चल रहे माहौल को लेकर कहा कि,मैं इस बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन देश में हर व्यक्ति सुखी रहे यह हमारे प्रधानमंत्री और भाजपा की मंशा है। समय और परिस्थितियों के कारण क्षणिक कोई चीजों का उदय होता है। इस देश में स्थाई तो वही रहता है जहां लगातार काम होता है और जहां लगातार देशवासियों का विश्वास रहता है।

राहुल गांधी के बयान पर जताया कड़ा ऐतराज- कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि वे प्रतिपक्ष के नेता हैं। एक जिम्मेदार नेता के नाते उन्हें अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने कहा, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री, जिनकी लोकप्रियता पूरे विश्व में है और जो भारत को स्वर्णिम युग में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनके प्रति ऐसे शब्दों का उपयोग करना बेहद निंदनीय है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी एक बार अपने नेतृत्व के बारे में आत्ममंथन करना चाहिए।

निगम-मंडल नियुक्तियों पर बोले- थोड़ा विश्राम दीजिए- निगम-मंडलों में बाकी बची नियुक्तियों को लेकर मीडिया के सवाल हेमंत खंडेलवाल ने मुस्कुराते हुए कहा, 10-15 साल बाद कई प्राधिकरण शुरू किए गए हैं। थोड़ा विश्राम दीजिए, आराम दीजिए, बाकी बची नियुक्तियां बाद में करेंगे।

कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत करना उद्देश्य- भाजपा की कार्यप्रणाली पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि पार्टी सतत रूप से प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करती है ताकि कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, राजनीतिक उद्देश्य और संगठन की कार्यशैली की गहरी जानकारी मिल सके। देशभर में अब तक लगभग 75 लाख कार्यकर्ता इन वर्गों में प्रशिक्षित हो चुके हैं और वर्तमान में इसका दूसरा चरण चल रहा है।

प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने गए थे

भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण वर्ग का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रशिक्षण वर्ग में लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।

मप्र में कॉकरोच पार्टी की एंट्री, भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस

कहा- यह आंदोलन शिथिल सिस्टम के खिलाफ नीट पेपर लीक प्रभावित, युवा भी मेंबर

भोपाल (नप्र)। कॉकरोच जनता पार्टी (भाजपा) की मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई है। भोपाल में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा कार्यकर्ता मयंक ने शुक्रवार को पार्टी के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान नीट पेपर लीक प्रभावित युवा, नर्सिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी से प्रभावित छात्राएं भी मौजूद रहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मयंक ने कहा कि सीजेपी केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि 'जेन जेड' की प्राथमिकताओं पर आधारित युवा आंदोलन है। यह किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के विरोध का मंच नहीं, बल्कि उस शिथिल सिस्टम के खिलाफ आवाज है, जिसने युवाओं का भरोसा तोड़ा है।

युवा सवाल उठाते हैं, तो दबाने की कोशिश होती है- उन्होंने आरोप लगाया कि जब पेपर लीक जैसे मामलों पर युवा सवाल उठाते हैं, तब उनकी आवाज दबाने और सोशल मीडिया अकाउंट्स तक बैन करने की कोशिश होती है। अब सरकारी संस्थान अपनी नैतिक जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। मयंक ने बताया कि जल्द ही मध्य प्रदेश की कोर कमेटी घोषित की जाएगी। विदेशी फॉलोअर्स और पाकिस्तानी अकाउंट्स से जुड़े आरोपों को सरकारी दुष्प्रचार बताया। उनका कहना था कि आंदोलन के संस्थापक अभिजीत दीपके के मार्गदर्शन में प्रदेश में अभियान की शुरुआत की गई है।

प्रदेश के 4 जिलों में तेज लू का रेड अलर्ट

46 डिग्री के पार जा रहा तापमान, अगले 10 दिन इससे भी ज्यादा गर्मी रहेगी

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी पड़ रही है। सुबह 9 से 11 बजे के बीच पारा 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 से तीन बजे तक बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार, अगले 10 दिन यानी 31 मई तक गर्मी का यह दौर अपने पीक पर रहेगा। शुक्रवार को निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जगहों पर पारा 46 डिग्री के पार जाने की आशंका है।

आज इन जिलों में हीटवेव का अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रदेश के 41 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है।

4 जिलों में रेड अलर्ट : निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट है। यहां तापमान 46 डिग्री के पार जा सकता है।

21 जिलों में तीव्र लू का ऑरेंज अलर्ट: ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, आगर-मालवा, राजगढ़, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, उमरिया, शहडोल, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

20 जिलों में लू का येलो अलर्ट: भोपाल, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, शाजापुर, रायसेन, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और अनूपपुर में येलो अलर्ट है। यहां तापमान 43 से 45 डिग्री के आसपास रहेगा।

9 जिलों में तेज गर्मी: इंदौर, देवास, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, धार, बड़वानी, झाबुआ और आलीराजपुर में लू की सीधी चेतावनी तो नहीं है, लेकिन उमस और तेज गर्मी का दौर जारी रहेगा।

अगले तीन दिन ऐसा रहेगा मौसम- मौसम विभाग ने अगले तीन दिन यानी 25 मई तक के लिए गर्मी का फोरकास्ट जारी किया है।

दतिया में नाबालिग से दो बार दुष्कर्म, केस दर्ज

फोटो वायरल करने की धमकी देकर दूसरी बार रेप, पिता को जान से मारने की धमकी दी

दतिया (नप्र)। दतिया के बसई थाना में 17 साल की लड़की से युवक ने दो बार दुष्कर्म किया। नाबालिग की शिकायत पर गुरुवार देर रात पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शिकायत में युवती ने बताया कि आरोपी युवक ने पहले सुनसान रास्ते में युवती को पकड़कर दुष्कर्म किया और फोटो वीडियो बना लिए। बाद में फोटो वायरल करने की धमकी देकर दोबारा वारदात को अंजाम दिया। युवक ने परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।

पिता को जान से मारने की धमकी दी इसलिए चुप रही- पीड़िता ने बताया कि, करीब दो माह पहले वह दोपहर के समय खेत पर जा रही थी।

इसी दौरान वीरू अहिरवार पीछे से आया और उसका मुंह दबाकर पास की झाड़ियों में ले गया। वहां आरोपी ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने थप्पड़ मारते हुए उसे और उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी।

डर और बदनामी के भय से किशोरी ने यह बात किसी को नहीं बताई। पीड़िता के अनुसार 18 मई को आरोपी ने फिर रास्ते में रोक लिया और फोटो वायरल करने की धमकी देकर दोबारा दुष्कर्म किया। घटना के बाद किशोरी ने घर पहुंचकर अपने माता-पिता को पूरी बात बताई।

जीआईएस के सौंदर्यीकरण की जांच पूरी, घिरा भोपाल निगम

1.73 करोड़ रुपए के फाउंटेन लगाए; जांच में सिर्फ पाइप ही मिले

भोपाल (नप्र)। भोपाल में पिछले साल फरवरी में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) के सौंदर्यीकरण की जांच पूरी हो गई है। जीआईएस से पहले शहर को चमकाने के नाम पर नगर निगम ने 19 जगहों पर फाउंटेन लगाने में करीब 1 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन जांच में पूरा सौंदर्यीकरण मॉडल सवालों में घिर गया है।

नगरीय प्रशासन विभाग की जांच समिति को कई जगह महंगे गनमेटल वाल्व, फ्लावर जेट नोजल, कनेक्टर और एलईडी लाइट मौके पर मिली ही नहीं। उनकी जगह साधारण पीवीसी निपल और वाल्व थे। खास बात ये है कि ताज होटल के सामने रिकॉर्ड में दर्ज फाउंटेन मौके पर मिला ही नहीं।

निगम अफसरों ने दावा किया कि उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन यह नहीं बता सके कि आखिर वह कहां लगाया गया। कई जगहों पर निगम कर्मचारियों ने उपकरण चोरी होने की दलील दी, लेकिन उससे जुड़े दस्तावेज तक नहीं दिखा सके। शिकायत लोकायुक्त तक पहुंचने के बाद हुई जांच में भुगतान और मौके की स्थिति में बड़ा अंतर सामने आया है।

निगम की सफाई- चोरी हो गए- पॉलीटेक्निक चौराहा, यातायात चौराहा और भारत माता चौराहे पर निगम कर्मचारियों ने जांच समिति को बताया कि नोजल चोरी हो गए हैं। हालांकि, इससे जुड़े कोई दस्तावेज या शिकायत पेश नहीं की गई। अफसरों का कहना है कि लोकायुक्त द्वारा जीआईएस से संबंधित जो रिपोर्ट मांगी गई थी, उसे भेज दिया है। आगे कोई निर्देश आते हैं तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

ताज होटल के सामने फाउंटेन ही नहीं मिला- जांच समिति जब ताज होटल के सामने पहुंची तो वहां फाउंटेन स्थापित नहीं मिला। निगम अफसरों ने दावा किया कि इसे दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, लेकिन नई लोकेशन नहीं बता सके।

आईएसबीटी समेत कई जगह सस्ती फिटिंग- मानव संग्रहालय, आईएसबीटी, प्रणामी मंदिर, भदभदा और एयरपोर्ट रोड पर नोजल और कनेक्टर गायब मिले। इनके स्थान पर साधारण पीवीसी निपल और वाल्व लगे पाए गए। एयरपोर्ट सेंट्रल वर्ज पर गनमेटल वाल्व की जगह पीवीसी वाल्व मिले।

कई फाउंटेन में एलईडी लाइट तक गायब

एयरपोर्ट मेन रोड पर एक भी एलईडी लाइट नहीं लगी मिली। लालघाटी चौराहे पर एलईडी टूटी और खराब हालत में मिलीं। बोर्ड ऑफिस और एयरपोर्ट ब्रिज के पास फाउंटेन बंद हालत में मिले।